

सक्ती में खौफनाक वारदात : नकाबपोश हमलावरों की फायरिंग में युवक की मौत, भाई घायल

नई दृष्टिबिंदु / सक्ती

छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में देर रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जब तीन नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर दो सगे भाइयों पर गोली चला दी। घटना किरां थाना क्षेत्र के करही गांव की है, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई।

जानकारी के अनुसार, हमलावर अचानक घर में दाखिल हुए और 19 वर्षीय आयुष कश्यप को निशाना बनाते हुए उसके सिर और सीने पर गोली दाग दी, जिससे उसकी मौत के घर ही मौत हो गई।



वहीं उसके छोटे भाई आशुतोष कश्यप को भी गोली लगी, जो कंधे में लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी घर से नकदी और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए तथा बाहर से दरवाजा बंद कर दिया।

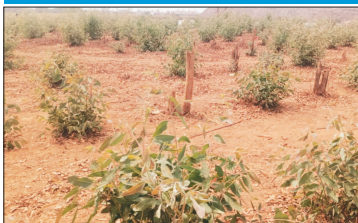
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और

घटनास्थल का जायजा लेकर जांच शुरू कर दी है। फरार आरोपियों की तलाश में इलाके में सघन सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा।

घटना की खबर मिलते ही जैजपुर विधायक बालेश्वर साहू अस्पताल पहुंचे और घायल युवक का हालचाल जाना। उन्होंने घटना पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि यह अत्यंत निंदनीय घटना है और दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया।

6 हजार पेड़ों की अवैध कटाई से हड़कंप, कलेक्टर के निरीक्षण में खुला मामला

8-10 एकड़ में सिर्फ टूट मिले, बिना अनुमति पेड़ कटने पर वन और राजस्व विभाग घेरे में



नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

जामुल रेंजिंग ग्राउंड के पास बड़े पैमाने पर पेड़ों की अवैध कटाई का मामला सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। रस्तोगी नामक व्यक्ति द्वारा करीब 6 हजार नीलगिरी के पेड़ काटे जाने की बात सामने आई है। यह पूरी कार्रवाई बिना वन विभाग और राजस्व विभाग की अनुमति के किए जाने की आशंका जताई जा रही है।

मामले का खुलासा उस समय हुआ, जब कलेक्टर सेग्रीग्राउंड प्लांट के निरीक्षण के लिए जामुल क्षेत्र पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने करीब 8 से 10 एकड़ क्षेत्र में बड़ी संख्या में पेड़ों के टूट देखे, जबकि पेड़ पूरी तरह गायब थे। इस पर कलेक्टर ने तत्काल जांच के निर्देश दिए।

कलेक्टर के निर्देश के बाद एसडीएम ने तहसीलदार को जांच के आदेश दिए। तहसीलदार ने जामुल के पटवारी को मौके पर भेजा, लेकिन आरोप पर जांच कार्रवाई ने विस्तृत जांच करने के बजाय सिर्फ पंचनामा तैयार कर टुट गिरने की



औपचारिक रिपोर्ट बना दी और उसे तहसीलदार को सौंप दिया। इससे पूरे मामले को दबाने की आशंका भी जताई जा रही है।

सूत्रों के अनुसार जिस जमीन पर पेड़ों की कटाई हुई है, उसे निजी भूमि बताया जा रहा है। हालांकि वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि किसी भी प्रकार के पेड़, चाहे वह निजी जमीन पर ही क्यों न हों, काटने से पहले संबंधित विभागों से अनुमति लेना अनिवार्य होता है। बिना अनुमति इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई गंभीर उल्लंघन है।

वहीं, राजस्व विभाग के अधिकारी इस मामले में स्पष्ट जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं। उनके बयान गोलमोल हैं, जिससे संदेह और गहरा गया है कि कहीं न कहीं मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इस घटना ने न सिर्फ प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि पर्यावरणीय नियमों को अंधेरे की ओर धकेल दिया है। अवैध कटाई का जो नुकसान हो रहा है, उसे देखना होगा कि जांच पर भेजा, लेकिन आरोप पर जांच कार्रवाई ने विस्तृत जांच करने के बजाय सिर्फ पंचनामा तैयार कर टुट गिरने की



बंगाल चुनाव : पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान का दावा, 91 लाख वोट कटने पर सियासी संग्राम



विशेष संवाददाता संदीप सिंह / कोलकाता

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण में 23 अप्रैल को 152 सीटों पर मतदान के साथ ही सियासी संग्रामों चरम पर पहुंच गई हैं। रिकॉर्ड 91.3 प्रतिशत मतदान के दावे, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत बड़ी संख्या में वोटों के नाम कटने और कई सीटों पर कड़े मुकाबले की स्थिति ने चुनाव को बेहद दिलचस्प और संवेदनशील बना दिया है।



हालांकि, अंतिम चरण का मतदान प्रतिशत की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है।

पहले चरण में कुल 1,478 प्रत्याशी मैदान में हैं और उत्तर बंगाल से लेकर जंगलमहल तक कई सीटें हाउसफुल बनी हुई हैं। कूचबिहार दक्षिण और इटाहार में सर्वाधिक 15-15 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि नंदीग्राम जैसी सीट पर भी बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है।

चुनाव के बीच सबसे बड़ा विवाद SIR

को लेकर खड़ा हुआ है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, राज्य में करीब 90.83 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, जिससे कुल मतदाताओं की संख्या 7.66 करोड़ से घटकर 7.04 करोड़ रह गई है। इनमें लगभग 27.16 लाख मतदाताओं की सुनवाई नहीं होने का आरोप भी लगाया जा रहा है। खास बात यह है कि 44 ऐसे सीटें सामने आई हैं, जहां हटाए गए मतदाताओं की संख्या पिछली बार की जीत के अंतर से अधिक बताई जा रही है, जिससे चुनाव परिणामों पर सीधा असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है।

नंदीग्राम सीट, जहां 2021 में सुवेदु अधिकारी ने महज 1,736 वोट से जीत दर्ज की थी, वहां इस बार 3,000 से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से बाहर होने की चर्चा है। वहीं भवानीपुर, जो ममता बनर्जी की परंपरागत सीट मानी जाती है, वहां भी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। ऑल इंडिया गुगुलु कांग्रेस ने इसे सुनिश्चित तरीके से वोटों को बाहर करने की साजिश बताया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि मतदाता सूची से केवल फजी नाम हटाए गए हैं। इस बीच, पहले चरण में मतदान प्रतिशत में संभावित बढ़ोतरी और मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर बदलाव ने चुनावी समीकरणों को जटिल बना दिया है। दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को 142 सीटों पर होना है, जिससे पहले चरण के रणनीति के आधार पर राजनीतिक दल अपनी रणनीति में बदलाव करने की तैयारी में जुट गए हैं।



दुर्ग में अवैध गुटखा फैक्ट्री का पर्दाफाश : 13 पकड़ाए



नंदिनी थाना क्षेत्र में चल रहा था जर्दा निर्माण का गोरखधंधा

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

जिले के नंदिनी थाना क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित गुटखा निर्माण फैक्ट्री पर दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। लंबे समय से गुप्त रूप से संचालित इस फैक्ट्री में प्रतिबंधित जर्दा युक्त गुटखा तैयार कर बाजार में खपाया जा रहा था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि क्षेत्र में एक मकान के भीतर अवैध रूप से गुटखा और जर्दा बनाने का काम चल रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से छापेमारी की, जहां मौके पर मुसाफिर ब्रांड का जर्दा युक्त गुटखा और एन4 ब्रांड का सुगंधित जर्दा बड़े पैमाने पर तैयार किया जा रहा था।

छापे के दौरान फैक्ट्री के भीतर काम कर रहे 13 मजदूर भी पुलिस के हथके चढ़े। पुछताछ में सामने आया कि ये मजदूर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से लाकर यहां काम पर लगाए गए थे। फैक्ट्री में गुटखा निर्माण, पैकिंग और सप्लाय का पूरा सेटअप तैयार था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह संगठित रूप से चलाया जा रहा कारोबार था। मौके से भारी मात्रा में तैयार गुटखा, कच्चा माल, पैकिंग सामग्री और मशीनों का जर्दा जमा है। पुलिस का अनुमान है कि यहां से बड़े स्तर पर अवैध गुटखा बाजार में सप्लाय किया जा रहा था, जिससे

न केवल राजस्व को नुकसान हो रहा था, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा था।

प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि फैक्ट्री अप्रैल मास की शुरुआत से लगातार संचालित हो रही थी। इस दौरान बिना किसी लाइसेंस और सुरक्षा मानकों के उत्पादन किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी मौके पर बुलाया, जिन्होंने खाद्य सुरक्षा मानकों के तहत सैंपल लेकर जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फैक्ट्री संचालकों और इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। जल्द ही पूरे नेटवर्क का खुलासा कर संबंधित आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।



भिलाई में महिलाओं को स्वरोजगार की राह, सर्व समाज कल्याण समिति का प्रशिक्षण अभियान तेज

दोना-पतल से लेकर सिलाई-कढ़ाई तक, सैकड़ों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सर्व समाज कल्याण समिति भिलाई द्वारा ग्रोष्पकालीन स्वरोजगार प्रशिक्षण शिविरों का संचालन किया जा रहा है। नगर निगम क्षेत्र के प्रवास आंध्र पाठशाला, सड़-29 में आयोजित इस प्रशिक्षण में महिलाएं घरेलू कार्यों से समय निकालकर उत्पादक बल बन रही हैं।

प्रशिक्षण के दौरान श्रीमती डी. लक्ष्मी एवं विमला सेनापति को दोना-पतल बनाने की मशीन चलाकर प्रशिक्षण दिया गया, साथ ही मशीन संचालन के दौरान आवश्यक सुरक्षा उपायों की भी जानकारी दी गई। शिविर में अब तक 87 महिलाओं ने सिलाई, कढ़ाई एवं अन्य कार्यों के लिए पंजीयन कराया है। प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक सिलाई मशीन का प्रशिक्षण दिया



जा रहा है, जिसमें 20-20 महिलाओं के समूह बनाकर प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा ही प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सर्व समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह छोट्टे के मार्गदर्शन में चल रहे

इस अभियान के लिए सैकड़ों आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। आसपास के क्षेत्रों की महिलाएं भी रोजगार से जुड़े विभिन्न प्रशिक्षणों के लिए अपनी रुचि साझा कर रही हैं, जिन पर लगातार कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम



में छत्तीसगढ़ भोजपुरी परिषद द्वारा आयोजित सम्मान समारोह एवं दो दलीय बैठक कार्यक्रम हेतु परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष

प्रमुनाथ बैठा एवं पदाधिकारियों द्वारा आमंत्रण प्राप्त हुआ, जिसके लिए आभार व्यक्त किया गया।

वहीं कोहका स्थित समिति कार्यालय में क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों, वरिष्ठजनों, माताओं-बहनों एवं युवाओं से आत्मीय संवाद भी किया गया। इस दौरान विभिन्न सामाजिक एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के निर्माण प्राप्त हुए। समाजिक सुदृढ़ के तहत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कल्याण मोर्चा के प्रदेश महामंत्री एवं दुर्ग नगर निगम के वरिष्ठ पार्षद साजन जोरफ को जन्मदिन की बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की गईं। महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार के क्षेत्र में यह पहल भिलाई में नई संभावनाओं का मार्ग खोल रही है, जिससे इंद्रजीत सिंह छोट्टे एक सक्रिय समाजसेवी के रूप में मजबूत पहचान बना रहे हैं।

अर्चना

फलाई ऐश ब्रिक्स

निर्माता एवं विक्रेता

हेवी इंडस्ट्रीयल एरिया, भिलाई

8 इंच एवं 9 इंच में उपलब्ध है।

संपर्क करें

9329960605, 9827160605, 9098639991

पाटन क्षेत्र के दो उपकेंद्रों में अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर ऊर्जीकृत, हजारों उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ

3488 घरेलू और 993 कृषि उपभोक्ताओं को ओवरलोडिंग की समस्या से मिलेगी मुक्ति

नई दृष्टि बिंदु / दुर्ग

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, दुर्ग क्षेत्र के विद्युत अधोसंरचना को मजबूती प्रदान करते हुए दिनांक 22 अप्रैल 2026 को पाटन विद्युत संभाग के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण स्थानों पर नए पावर ट्रांसफार्मर सफलतापूर्वक कार्य किए गए। पाटन वितरण केंद्र के 33/11 केवी उपकेंद्र फुंडा और जामगांव (टी) वितरण केंद्र के 33/11 केवी उपकेंद्र घुघवा में 3.15 एमवीए क्षमता के अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए।

इन दोनों उपकेंद्रों में पहले से ही 3.15 एमवीए के ट्रांसफार्मर स्थापित थे, जिनमें अब अतिरिक्त क्षमता विस्तार किया गया है। उक्त दोनों उपकेंद्रों में स्थापित हुए अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर को कार्यपालक निदेशक (दुर्ग क्षेत्र) संजय खंडेलवाल द्वारा ऊर्जीकृत किया गया, जिससे दोनों उपकेंद्रों की क्षमता बढ़कर 6.30 एमवीए हो गई है।



की क्षमता बढ़कर 6.30 एमवीए हो गई है।



परियोजना का सीधा लाभ क्षेत्र के हजारों उपभोक्ताओं को मिलेगा। इस विस्तार से पाटन वितरण केंद्र के ग्राम फुंडा, पुनाइदिह, अरसनारा, देवादा, सातरा सहित

जामगांव (टी) वितरण केंद्र के घुघवा, करसा, बेंद, राखी, रवेली, अमरे, भभरा, और छोट व चढ़े औरी जैसे क्षेत्रों की विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ होगी। इससे न केवल 3488 घरों और 993 कृषि उपभोक्ताओं की ओवरलोडिंग की समस्या से मुक्ति मिलेगी, बल्कि उन्हें भविष्य में समुचित वोल्टेज और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।

इस महत्वपूर्ण तकनीकी कार्य के दौरान विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं तकनीकी टीम मुख्य रूप से उपस्थित रही। ट्रांसफार्मर को ऊर्जीकृत करने की प्रक्रिका अधीक्षक अभियंता (दुर्ग वृत्त) आर.के. मिश्रा, कार्यपालन अभियंता बी.पी. दीपक, धर्मेन्द्र भारती एवं एस.के. राय की उपस्थिति में संपन्न हुई। सहायक अभियंता दुर्जेंद्र गजपाल, कमलेश साहू, डी.के. साहू एवं अन्य तकनीकी स्टाफ ने इस कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने में सक्रिय योगदान दिया।

खास खबर

शुद्ध पेयजल के लिए पूर्व में स्थापित वाटर एटीएम का डीएफएम राशि से जल्द संधारण कराने की मांग



नई दृष्टि बिंदु / भिलाई

जन स्वास्थ्य को लेकर विधायक कलेक्टर को लिखा पत्र

टाउनशिप क्षेत्र में मटमैला और बदनबूदार पानी आपूर्ति की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। इस और पत्र और ज्ञान के माध्यम से लगातार बीएसपी प्रबंधन को अवगत कराया जा रहा है, लेकिन प्रबंधन ध्यान नहीं दे रहा है। इससे लोगों को स्वास्थ्ययज्ञ समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या से जुड़ा रही लोगों को राहत दिलाने के लिए भिलाई नगर विधायक देवेन्द्र यादव ने पहले की है। उन्होंने कलेक्टर दुर्ग को पत्र के माध्यम से लोगों की समस्या से अवगत कराया है और जिला खनिज न्याय मद से पूर्व में स्थापित वाटर एटीएम मशीनों का संधारण जल्द से जल्द कराने की मांग की है। ताकि लोगों को पहले की वाटर एटीएम से शुद्ध पेयजल मिल सके।

विधायक ने पत्र में लिखा है कि भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र के रेलम ऐरिया और टाउनशिप क्षेत्र के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पिछले 2-3 वर्षों में विभिन्न स्थानों पर वाटर एटीएम लगाये थे। एक समय के बाद इन मशीनों का संधारण की आवश्यकता है और कई मशीनें संधारण के अभाव में खराब हो गई हैं जिससे लोगों को साफ पानी नहीं मिल पा रहा है और वे मजबूरन मटमैला व बदनबूदार पानी उपयोग कर रहे हैं। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि मशीनों के संधारण और मरम्मत को लेकर नगर निगम को पहले भी अवगत कराया गया था, लेकिन अब तक कोई ज़ोर कार्रवाई नहीं हुई है। इसका चलते स्थानीय जनप्रतिनिधियों और वार्डवासियों में काफी नाराजगी है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विधायक देवेन्द्र यादव ने कलेक्टर से आग्रह किया है कि प्रीमकाल में पेयजल संकट को ध्यान में रखते हुए जिला खनिज न्याय मद से सभी खराब वाटर एटीएम मशीनों को मरम्मत और संधारण कार्य जल्द स्वीकृत कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके।

निकिता को मिली डॉक्टर की उपाधि

भिलाई : नगर के वार्ड क्रमांक 1 निवासी निकिता मिश्रा ने हेमचंद्र विश्वविद्यालय से बायोटेक्नोलॉजी विषय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर क्षेत्र का नाम गौरवान्वित किया है। उन्होंने इन विद्वत् कवरेजेशन ऑफ डिप्लोमाइंडकॉलेज पालमेट्स सी. जेकरे थ्रूवेरिस अर्थ विषय पर अपना शोधकार्य पूर्ण किया। निकिता ने यह शोधकार्य तत्वांथा स्थित सेंट थॉमस कॉलेज में सुपुवाइजर डॉ. उज्ज्वला सूर्य के मार्गदर्शन में संपन्न किया, जिसमें विभागाध्यक्ष डॉ. वी. सांता एवं कालेज की प्रचार्य डॉ. शाइली गेंडोस का विशेष सहयोग रहा। (निकिता मिश्रा नगर के वरिष्ठ पत्रकार संदीप मिश्रा एवं श्रीमती मंजू मिश्रा की सुपुत्री हैं। साथ ही वे पाटन निवासी अधिवक्ता शुभम ठाकुर की पत्नी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश ठाकुर की पुत्रवधू हैं। वे अंकिता ठाकुर को छोटी बहन तथा परिणीता मिश्रा की बड़ी बहन हैं तो इससे अलावा निकिता शुभप्रतिष्ठ ठाकुर की माता जी हैं।)

दुर्ग में राशन व्यवस्था फेल, जनता की पुकार पर पहुँचे वारा

नई दृष्टि बिंदु / दुर्ग

तपती गर्मी और बढ़ती परेशानियों के बीच, पूर्व वरिष्ठ विधायक अरुण वारा एक बार फिर जनसेवा की मिसाल पेश करते हुए सीधे जनता के बीच पहुँचे। वार्ड क्रमांक 3, 4, 52 (बोरसी) और 56 (बबरा) में राशन दुकानों पर चालू की गंभीर ममी की शिकायत मिलते ही वे स्वयं मौके पर पहुँचे और स्थिति का जायजा लिया।

स्थानीय नागरिकों ने बताया कि पिछले कई दिनों से दुर्ग राशन नहीं मिल पा रहा है, जिससे दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। भोषण गंभीर (43-45 डिग्री) में लोग राशन के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं। इस पर वारा ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों से चर्चा की और स्पष्ट निर्देश दिए कि समस्या का समाधान तत्काल सुनिश्चित किया जाए।

राशन दुकानदारों ने भी गंभीर स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि दुर्ग शहर, भिलाई एवं दुर्ग ग्रामीण क्षेत्रों की कुल लगभग 327 राशन दुकानों में पिछले तीन महीनों से आपूर्ति बाधित है। यह व्यापक समस्या शासन-प्रशासन की कार्यक्षमता पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। वारा ने इस लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जनता को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखना किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है। प्रशासन को तुरंत सक्रिय होकर आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी। क्षेत्रवासियों ने भी वारा की तत्परता और संवेदनशीलता की सराहना की। लगातार वार्डों में पहुँचकर समस्याओं को सुनना और उनके समाधान के लिए प्रतिबद्ध रहना, उनके जनप्रतिनिधि होने की सच्ची पहचान को दर्शाता है।

जिला पंचायत दुर्ग सीईओ ने ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण

नई दृष्टि बिंदु / दुर्ग

जिला पंचायत दुर्ग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) बजरंग कुमार दुबे ने विकासखंड धमधा अंतर्गत ग्राम पंचायत परसदा एवं बिरभाट की निरीक्षण कर विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने विशेष रूप से मालत्या गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चल रहे कार्यों की स्थिति की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत परसदा में अमृत सरोवर निर्माण, वृक्षाणुरण, तरा नाली गहराकरण, सरार गहराकरण एवं जल संरक्षण से जुड़े कार्यों का अवलोकन किया गया। सीईओ ने मौके पर मौजूद मजदूरों से चर्चा कर कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति की जानकारी ली।

उन्होंने कार्यस्थल पर प्रस्तावित दो नाली निर्माण कार्यों की जानकारी लेते हुए मस्टर प्लान की अंतिमलाइन उपस्थिति और एम.पी. बुक (मेजरजट बुक) का भी परीक्षण किया। साथ ही परकोलेशन टेक निर्माण के लिए आवश्यक निर्देश दिए।

सीईओ दुबे ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी निर्माण कार्यों को समयसमय में पूर्ण करते हुए गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि ग्रामीणों को योजनाओं का अधिकतम लाभ मिल सके।

मोहन नगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: अवैध हुक्का व ई-सिगरेट बिक्री का भंडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार

नई दृष्टि बिंदु / दुर्ग

नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत मोहन नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से हुक्का एवं इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बेचने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों सहित बड़ी मात्रा में सामग्री जप्त की है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 22 अप्रैल 2026 को मुखबिरी से सूचना प्राप्त हुई थी कि मालवीय नगर स्थित जैन मंदिर के सामने एक दुकान में अवैध रूप से हुक्का से जुड़े तंबाकू उत्पाद और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का भंडारण कर बिक्री की जा रही है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए



मोहन नगर थाना पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दुकान की ध्विगत तलाशी ली। तलाशी के दौरान प्लास्टिक बोरेजों में रखे 55 पैकेट हुक्का फ्लेवर, 40 नग इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, 4 पैकेट हुक्का नोजल, 4 पैकेट हुक्का और 600 नगद बरामद किए गए। जप्त सामग्री की कुल अनुमानित कीमत 1,02,100 बताई गई है। इस मामले में पुलिस ने राजेश जैन (38 वर्ष) और शैलेश जैन (36 वर्ष), दोनों निवासी मालवीय नगर, दुर्ग को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 21(1), 4 तथा इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम 2019 की धारा 7 के तहत अपराध दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, आरोपी प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की अवैध बिक्री कर आर्थिक लाभ अर्जित कर रहे थे। इस पूरी कार्रवाई में मोहन नगर थाना पुलिस टीम को सहायनीय भूमिका रही। दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि ऐसे अवैध नशे के कारोबार की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि दीर्घियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।

तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने वाला युवक गिरफ्तार

दुर्ग। जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस थाना क्षेत्र में पुलिस ने तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने निजी वाहन में अवैध रूप से पुलिस मोनो और बोर्ड लगाकर आम लोगों को भ्रमित कर रहा था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 23 अप्रैल 2026 को चौकी स्थिति नगर क्षेत्र अंतर्गत जुवावाली चौक के पास एक थार वाहन चालक द्वारा तेज गति और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने की सूचना प्राप्त हुई थी। साथ ही वाहन में अवैध रूप से पुलिस लिखा बोर्ड लगाए जाने की भी शिकायत मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और वाहन को रोककर जांच की। जांच में चालक का कृत्य प्रथम दृष्टया अपराध पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 555/2026 के तहत धारा 281 बौध्दयस और धारा 184 मोटर वाहन अधिनियम में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान समीर चर्मा (23 वर्ष), निवासी आर्य नगर कोठका के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से काले रंग की थार (वाहन क्रमांक CG 07 CP 8800) को जल कर लिया है और मामले में आगे की जांच जारी है। पुलिस के अनुसार, आरोपी तेज गति और लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने के साथ-साथ अवैध रूप से पुलिस चिन्ह का उपयोग कर भ्रम उत्पन्न कर भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा था, जिससे आमजन की जान खतरा उत्पन्न हो रहा था।

अधिकारी जनता के बीच जाएं और करें संवाद – राज्यपाल डेका, जल संरक्षण के लिए डबरी का करें निर्माण

राज्यपाल ने ली रायपुर जिले में विकासखंड स्तरीय समीक्षा बैठक, नशे पर सख्ती से रोक लगाए एवं भारी वहनों के आवामगम पर करें नियंत्रण

नई दृष्टिविंदु / रायपुर

राज्यपाल रमेन डेका ने रायपुर जिले की विकासखण्ड स्तरीय समीक्षा बैठक की। राज्यपाल ने कहा कि सभी अधिकारी जनता बीच जाएं और उनसे मिलें। उनके तथा हिताहितवासी से मुलाकात करें एवं उनकी समस्याओं की जानकारी लेकर योजनाओं का फीडबैक लें। उन्होंने कहा कि जमीनी हकीकत जानने का सबसे बेहतर तरीका लोगों से लगातार संवाद है। राज्यपाल ने जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे प्रोजेक्ट अना, प्रोजेक्ट ग्रीन पालना और प्रोजेक्ट रचना को सराहा।

श्री डेका ने जिले के विभिन्न विकासखण्डों में हो रहे डबरी निर्माण को भी सराहा करते हुए कहा कि हमें बड़े किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, इससे न्यूपुर के जलस्तर में सुधार आएगा और भविष्य में होने वाले

संभावित पेयजल की समस्या का सामना करने में सहायता मिलेगा। उन्होंने अन्य रायपुरों के सफल मॉडलों का उल्लेख करते हुए अधिकारियों को व्यवहारिक और प्रभावी उपाय अपनाने की सलाह दी। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में धान की खेती अधिक होती है, जो पानी की खपत बढ़ाती है, इसलिए बड़े किसानों को अन्य फसलों की और भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

राज्यपाल ने कहा कि रायपुर तेजी से विकसित हो रहा है और आने वाले वर्षों में जल संरक्षण सबसे बड़ी आवश्यकता बन जाएगा। उन्होंने जल जागरूकता, संसाधनों के संरक्षण और उनके सही उपयोग पर विशेष जोर दिया। साथ ही निर्देश दिए कि प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर जल स्रोतों का पुरा रिपोर्ट रखा जाए, ताकि उसी आधार पर बेहतर योजना और रणनीति बनाई जा सके।

श्री डेका ने कहा कि हमें ग्राम पंचायत स्तर पर छोटी-छोटी डबरी बनानी चाहिए। इस कार्य



में समुदाय की भागीदारी अवश्य सुनिश्चित करें और जनप्रतिनिधियों को भी ऐसे कार्यों के लिए शामिल करें। सभी शासकीय कार्यालयों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का निर्माण करें और अन्य लोगों को भी प्रोत्साहित करें। उन्होंने जल जागरूकता, संसाधनों के संरक्षण और उनके सही उपयोग पर विशेष जोर दिया। राज्यपाल ने कहा कि वृक्षारोपण को अधिक से अधिक बढ़ाया दें। एम्स, डॉ.

भीमवार अंबेडकर हॉस्पिटल एवं स्कूलों में वृक्षारोपण करें। सड़कों के किनारे भी वृक्षारोपण किया जा सकता है, इससे प्रदूषण को रोकथाम में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि विकास की निशानी अधिक से अधिक पेड़ लगाना और हरिवाली है।

प्रोजेक्ट हर घर मुनगा की समीक्षा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि जैविक और प्राकृतिक तरीके करने वाले किसानों को प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने कहा कि जैविक खेती को बढ़ावा दें, नेचुरल फार्मिंग में वैल्यू एडिशन जरूरी है। हमें विशेष रूप से हाइड्रोपोनिक्स को बढ़ावा देना चाहिए। आने वाला समय में इसकी अच्छी संभावना है। उन्होंने नर्सरी हाइड्रोपोनिक्स विकसित करने का सुझाव दिया। राज्यपाल परियोजना की चर्चा के दौरान राज्यपाल ने जानकारी ली कि नवप्रसूता महिलाओं को दिए गए पौधों की निगरानी कैसे होती है। वे जीवित है या

नहीं। राज्यपाल ने कहा कि पेड़ लगाना हम सभी की जिम्मेदारी है और हर व्यक्ति को कम से कम एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। राज्यपाल ने योग के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आम जनता से कहा कि योग की कक्षाओं तक ही सीमित न रहें बल्कि योग सौजन्य के वाद निर्वाचित रूप से घर में भी इसका अभ्यास करें।

यातायात व्यवस्था को राज्यपाल ने कहा कि जिले में भारी वहनों की नियंत्रित करने की आवश्यकता है। तीव्र गति से ड्राइविंग और हेल्मेट के मामले में पहले जागरूकता बढ़ाने और फिर आवश्यक होने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने नरें को बढ़ती समस्याएं चिंतित जाते हुए कहा कि सख्ती और जागरूकता के जरिए इसे रोकना जरूरी है। इस अवसर पर राज्यपाल की उपस्थिति सुश्री निधि साहू, जिले के प्रशासनिक अधिकारियों सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

खास खबर

राज्यपाल के निर्देश पर धनेशपुर में दिव्यांग बच्चों के लिए लगा विशेष शिविर



नई दृष्टिविंदु / रायपुर

राज्यपाल रमेन डेका ने बलरामपुर जिले के कुसमी विकासखंड अंतर्गत ग्राम धनेशपुर में दिव्यांग बच्चों के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। शिविर समाज कल्याण विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग संयुक्त रूप से आयोजित कर जलसंतर्पित दिव्यांगजनों का उपचार कर आवश्यक उपकरण प्रदान करें। राज्यपाल ने कहा है कि दोनों विभाग आपसी समन्वय से ग्राम धनेशपुर में विशेष शिविर आयोजित करें, जहां दिव्यांग बच्चों की स्वास्थ्य जांच, आवश्यक परीक्षण तथा उनकी स्थिति का आकलन किया जाए। साथ ही दिव्यांगता के संभावित कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत सर्वे एवं चिकित्सकीय अध्ययन भी कराया जाए।

निशानुसार समाज कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग को संयुक्त टीम गांव पहुंचकर घर-घर सर्वे करेंगी तथा पात्र बच्चों और नागरिकों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं दिव्यांगता कार्ड बनाने की प्रक्रिया भी सुनिश्चित करेंगी। शिविर के माध्यम से जरूरतमंद बच्चों को सहायक उपकरणों का वितरण भी किया जाएगा, ताकि उन्हें दैनिक जीवन, शिक्षा और आवागमन में सुविधा मिल सके। राज्यपाल ने अधिकारियों से कहा कि दिव्यांगता से प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए तथा बच्चों के बेहतर उपचार, गुणवत्ता और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए टीम कार्ययोजना बनाई जाए।

महड़ीपखोल गुफा दर्शन के लिए प्रशासन ने की पूरी तैयार, सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाओं पर विशेष जोर



खैराबाद-छूईखदान-नईडों। जिले के विकासखंड छूईखदान के ठाकुरटोला जमींदारी में आगामी 27 अप्रैल को ऐतिहासिक गुफा मण्डीपखोल गुफा के खुलने के महेंजर जिला प्रशासन द्वारा व्यापक मण्डीपखोल गुफा की जा रही है। इसी क्रम में आज गुरुवार को जपद पंचायत छूईखदान के सभाकक्ष में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में विकासखंड स्तरीय अधिकारियों की विस्तृत बैठक आयोजित की गई। बैठक में ब्रह्मलुओं की संभावित बड़ी संख्या को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को संचालन प्रारम्भिकता देने के निर्देश दिए गए। गुफा क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, प्रभावी बीड नियंत्रण एवं सुरक्षित यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया, ताकि ब्रह्मलुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। स्वास्थ्य विभाग को गुफा स्थल पर अस्थायी चिकित्सा शिविर स्थापित करने, आपातकालीन सेवाओं को सक्रिय रखने तथा अतिरिक्त स्वास्थ्य टीम की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, जिससे किसी भी स्थिति में त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सके। ब्रह्मलुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त पेयजल, सफा-सफाई, शौचालय एवं प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आयोजन समिति एवं ग्राम पंचायतों को आवश्यक निर्देश दिए गए। वहीं आबकारी विभाग को गुफा के आसपास एवं जलदोरी क्षेत्रों में मादक पदार्थ पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया। बैठक में डीआरपी, अनुविभागीय अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जपद पंचायत, मण्डीपखोल गुफा दर्शन आयोजन समिति के संस्रक्षक जल गैरिष्ठ सिंह प्लूराल एवं सदस्य, विभागीय अधिकारी तथा क्षेत्र के सरपंच एवं सचिव उपस्थित थे।

हर घर तक पोषण, हर महिला को आत्मनिर्भरता : मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े

नई दृष्टिविंदु / रायपुर

छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण और पोषण सुरक्षा की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। सूत्रजुग जिले के एकीकृत बाल विकास परियोजना रामानुजगर अंतर्गत ग्राम दरीपारा में बेलापूर्व महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा 90 लाख रुपये की लागत से स्थापित आधुनिक पोषण आहार उत्पादन यूनिट का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थीं। कार्यक्रम में विधायक भूलन सिंह मरावी सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य मौजूद रही।

मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार, प्रशासनमंत्री श्री नंद मोदी की गांठरी के अनुरूप महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और बच्चों एवं दूध पोषण आहार का उत्पादन किया जाएगा, जिससे बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं को समय पर गुणवत्तापूर्ण पोषण उपलब्ध हो सकेगा।



उत्पादन केन्द्र नहीं, बल्कि ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सशक्तिकरण का मजबूत आधार बननेगी। ग्राम दरीपारा में स्थापित इस अत्याधुनिक यूनिट के माध्यम से परियोजना रामानुजगर के 313 औपनगवाड़ी केन्द्रों को मोटा शक्ति आहार एवं पोषक नमकों दालिया की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। यूनिट में लगभग 30 मीट्रिक टन पोषण आहार का उत्पादन किया जाएगा, जिससे बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं को समय पर गुणवत्तापूर्ण पोषण उपलब्ध हो सकेगा।

यह पहल न केवल कुपोषण की चुनौती से निपटने में सहायक सिद्ध होगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सुनिश्चित करेगी। स्वयं सहायता समूह को महिलाएं एवं उत्पादन, पैकेजिंग, गुणवत्ता नियंत्रण, वितरण जैसे कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि आत्मनिर्भरता और स्थानीय उद्यमिता के विवेकीय संगम का उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभरी है। प्रशासन द्वारा इस प्रकार के नवाचारी प्रयासों को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी इस मॉडल को अपनाया जा सके।

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई के न्यायालय में माना

क्रमांक : 202604101000120

विषय :- अ-6 अ मामले की श्रेणी :- राजस्व सार - 2025-2026
क्रमांक प.ह.न. 00046/1 (रौ.)
पक्षकार का विवरण-आवेदक पक्षकार रतिराम, अनादेवक पक्षकार :-

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक अना देवी सात सिद्धांत विचार-व्यवस्था प्रदाय प्राप्त-विचारिता प्रतिविधान-कोष-व्यवस्था द्वारा प्राप्त-खेतीप्राप्त प.ह.न. रा.पि. में जिला सहायक न्यायालय व जिला दुर्ग की भूमि प्रस्ताव प.ह.न. 197/1 एवं प.ह.न. 41 किसे वेदोत्तर देवी सुधार किने जाने हेतु न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
एतद द्वारा सर्व साधारण किने जाने के अवसर पर प्रस्तुत किया गया है।
परिसर की भूमि का न्यायस्थान किने जाने पर निरा किरी की व्यक्ति संख्या को उजर दवा हो तो सुनुवाई निर्दिष्ट दिनांक 05.05.2026 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने नाम अधिकाधिक के साथ उपस्थित होकर अपना अधिकार प्रस्तुत कर सकते हैं। (निर्वाचित किने का नाम धारा आगमन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।)
यह इस्तेमाल मे हलाकर एवं परमदुर्ग से आज दिनांक 18/04/2026 को जारी किया जाता है।

दिकेयणर साहू
अतिरिक्त तहसीलदार, भिलाई नगर

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई के न्यायालय में माना

क्रमांक : 202604101000120

विषय :- अ-6 अ मामले की श्रेणी :- राजस्व सार - 2025-2026
क्रमांक प.ह.न. 00046/1 (रौ.)
पक्षकार का विवरण-आवेदक पक्षकार रतिराम, अनादेवक पक्षकार :-

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक अना देवी सात सिद्धांत विचार-व्यवस्था प्रदाय प्राप्त-विचारिता प्रतिविधान-कोष-व्यवस्था द्वारा प्राप्त-खेतीप्राप्त प.ह.न. रा.पि. में जिला सहायक न्यायालय व जिला दुर्ग की भूमि प्रस्ताव प.ह.न. 197/1 एवं प.ह.न. 41 किसे वेदोत्तर देवी सुधार किने जाने हेतु न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
एतद द्वारा सर्व साधारण किने जाने के अवसर पर प्रस्तुत किया गया है।
परिसर की भूमि का न्यायस्थान किने जाने पर निरा किरी की व्यक्ति संख्या को उजर दवा हो तो सुनुवाई निर्दिष्ट दिनांक 05.05.2026 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने नाम अधिकाधिक के साथ उपस्थित होकर अपना अधिकार प्रस्तुत कर सकते हैं। (निर्वाचित किने का नाम धारा आगमन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।)
यह इस्तेमाल मे हलाकर एवं परमदुर्ग से आज दिनांक 18/04/2026 को जारी किया जाता है।

दिकेयणर साहू
अतिरिक्त तहसीलदार, भिलाई नगर

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग

क्रमांक : 202604101000139/

विषय :- अ-6 अ मामले की श्रेणी :- राजस्व सार - 2025-2026
क्रमांक प.ह.न. 00046/1 (रौ.)
पक्षकार का विवरण-आवेदक पक्षकार रतिराम, अनादेवक पक्षकार :-

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक अना देवी सात सिद्धांत विचार-व्यवस्था प्रदाय प्राप्त-विचारिता प्रतिविधान-कोष-व्यवस्था द्वारा प्राप्त-खेतीप्राप्त प.ह.न. रा.पि. में जिला सहायक न्यायालय व जिला दुर्ग की भूमि प्रस्ताव प.ह.न. 197/1 एवं प.ह.न. 41 किसे वेदोत्तर देवी सुधार किने जाने हेतु न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
एतद द्वारा सर्व साधारण किने जाने के अवसर पर प्रस्तुत किया गया है।
परिसर की भूमि का न्यायस्थान किने जाने पर निरा किरी की व्यक्ति संख्या को उजर दवा हो तो सुनुवाई निर्दिष्ट दिनांक 05.05.2026 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने नाम अधिकाधिक के साथ उपस्थित होकर अपना अधिकार प्रस्तुत कर सकते हैं। (निर्वाचित किने का नाम धारा आगमन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।)
यह इस्तेमाल मे हलाकर एवं परमदुर्ग से आज दिनांक 18/04/2026 को जारी किया जाता है।

दिकेयणर साहू
अतिरिक्त तहसीलदार, भिलाई नगर

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग

क्रमांक : 202604101000139/

विषय :- अ-6 अ मामले की श्रेणी :- राजस्व सार - 2025-2026
क्रमांक प.ह.न. 00046/1 (रौ.)
पक्षकार का विवरण-आवेदक पक्षकार रतिराम, अनादेवक पक्षकार :-

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक अना देवी सात सिद्धांत विचार-व्यवस्था प्रदाय प्राप्त-विचारिता प्रतिविधान-कोष-व्यवस्था द्वारा प्राप्त-खेतीप्राप्त प.ह.न. रा.पि. में जिला सहायक न्यायालय व जिला दुर्ग की भूमि प्रस्ताव प.ह.न. 197/1 एवं प.ह.न. 41 किसे वेदोत्तर देवी सुधार किने जाने हेतु न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
एतद द्वारा सर्व साधारण किने जाने के अवसर पर प्रस्तुत किया गया है।
परिसर की भूमि का न्यायस्थान किने जाने पर निरा किरी की व्यक्ति संख्या को उजर दवा हो तो सुनुवाई निर्दिष्ट दिनांक 05.05.2026 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने नाम अधिकाधिक के साथ उपस्थित होकर अपना अधिकार प्रस्तुत कर सकते हैं। (निर्वाचित किने का नाम धारा आगमन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।)
यह इस्तेमाल मे हलाकर एवं परमदुर्ग से आज दिनांक 18/04/2026 को जारी किया जाता है।

दिकेयणर साहू
अतिरिक्त तहसीलदार, भिलाई नगर

पर्यटन व संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने किया नहर-जलाशय जीर्णोद्धार कार्यों का भूमिपूजन



राज्य सरकार की पहल से किसानों के खेतों तक पहुंचेगा भरपूर पानी, बड़ेगी सिंचाई क्षमता

नई दृष्टिविंदु / रायपुर

छत्तीसगढ़ में जल प्रबंधन और ग्रामीण अधोसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने आज अर्थिकापुर विधानसभा अंतर्गत उदयपुर विकासखंड में 520 लाख रूप से अधिक लागत के दो महत्वपूर्ण नहर-जलाशय जीर्णोद्धार कार्यों का भूमिपूजन किया। इनमें 265.99 लाख की लागत से डाम्नावा जलाशय बांध एवं नहर जीर्णोद्धार तथा 254.34 लाख रूप की लागत से पंडरीबांड जलाशय बांध एवं नहर जीर्णोद्धार कार्य शामिल हैं। यह मुख्यमंत्री

विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार की जल-प्रबंधन और अधोसंरचना विकास को प्राथमिकता देने वाली नीति का सशक्त उदाहरण है। भूमिपूजन के अवसर पर मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि जलाशयों और नहरों के सुदृढ़ीकरण से क्षेत्र की सिंचाई क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे किसानों को वर्षभर पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सकेगा। अन्तर्दत्ताओं को स्थायी सिंचाई सुविधा मिलने से वे बहुकृषि खेती को और अपसर होंगे, जिससे उत्पादन में वृद्धि के साथ उनकी आय में भी सीधा इजाफा होगा। उन्होंने बताया कि इस तरह की परियोजनाएं केवल खेतों तक पानी पहुंचाने का कार्य

नहीं करती, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने का माध्यम बनती हैं। जलाशयों और नहरों के जीर्णोद्धार से जल संचयन क्षमता बढ़ेगी और भू-जल स्तर में सुधार होगा, जिससे लंबे समय तक सिंचाई को स्थिर व्यवस्था बनी रहेगी। इससे धान के अलावा दलहन, तिलहन और बाजरा फसलों की भी बढ़ावा मिलेगा, जो कृषि विविधीकरण और बाजार आधारित खेती के लिए महत्वपूर्ण है। इससे किसानों की आय में स्थिरता आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। साथ ही पशुपालन और मत्स्य पालन जैसे सहायक गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था में

व्यापक सुधार देखने को मिलेगा। जल संकट में कमी आने से ग्रामीणों को पेयजल की बेहतर उपलब्धता होगी, वहीं महिलाओं को पानी लाने की कठिनाईओं से राहत मिलेगी। जलस्तर में सुधार और हरीहाली बढने से पर्यावरणीय संतुलन भी मजबूत होगा, जो क्षेत्र के समग्र विकास में सहायक सिद्ध होगा। भूमिपूजन के अवसर पर स्थानीय नागरिकों और किसानों ने सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में साय सरकार द्वारा किए जा रहे ऐसे प्रयास न केवल कृषि क्षेत्र को सशक्त बना रहे हैं, बल्कि ग्रामीण विकास और आर्थिक समृद्धि की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

शिक्षकों के समर्पण से ही होगा शिक्षा का सशक्त निर्माण – मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े

नई दृष्टिविंदु / रायपुर

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा है कि शिक्षकों का समर्पण ही एक सशक्त शिक्षा व्यवस्था की नींव है और उनके प्रयासों से ही समाज एवं राष्ट्र का भविष्य आकार लेता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल ज्ञानागार का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्तिगत निर्माण की आधारशिला है, जिसे मजबूत करने में शिक्षकों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मंत्री श्रीमती राजवाड़े जिला स्तरीय मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रही थीं, जिनसे राज्यभर में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों के सम्मान और प्रेरणा के रूप में देखा जा रहा है।



श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा को गुणवत्ता सुधारने के लिए निरंतर प्रयासरत है और इस दिशा में शिक्षकों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने शिक्षकों का आभान करते हुए कहा कि वे नवाचार, समर्पण और

संवेदनशीलता के साथ विद्यार्थियों को शिक्षित करें, ताकि बच्चे न केवल शैक्षणिक रूप से उत्कृष्ट बनें, बल्कि नैतिकता, अंशुभासन और जीवन कौशल से भी परिपूर्ण हों। मंत्री ने सम्मानित शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि ऐसे आयोजन

शिक्षकों के मनोबल को बढ़ाते हैं और उन्हें और बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। कार्यक्रम में विधायक भूलन सिंह मरावी ने भी शिक्षकों की भूमिका को सराहना करते हुए कहा कि विशेष रूप से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षक सीमित

संसाधनों के बावजूद उत्कृष्ट परिणाम दे रहे हैं। उन्होंने शिक्षकों से बच्चों की समग्र शिक्षा देने का आभान किया। समारोह के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी ने राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे सकारात्मक बदलावों की जानकारी देते हुए बताया कि नवाचार, सतत मूल्यांकन एवं विविध शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कार्यक्रम में उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया गया, जिससे पूरे वातावरण में उत्साह और गौरव का भाव देखने को मिला। इस प्रकार के आयोजन शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। समारोह में जनप्रतिनिधि, शिक्षादाता, शिक्षक एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

संसाधनों के बावजूद उत्कृष्ट परिणाम दे रहे हैं। उन्होंने शिक्षकों से बच्चों की समग्र शिक्षा देने का आभान किया। समारोह के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी ने राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे सकारात्मक बदलावों की जानकारी देते हुए बताया कि नवाचार, सतत मूल्यांकन एवं विविध शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कार्यक्रम में उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया गया, जिससे पूरे वातावरण में उत्साह और गौरव का भाव देखने को मिला। इस प्रकार के आयोजन शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। समारोह में जनप्रतिनिधि, शिक्षादाता, शिक्षक एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।





संपादकीय

केजरीवाल ने चला था दांव, फेल हो गया

यह सच है कि राजनीति में आरोपों का बड़ा महत्व होता है। राजनीति में रोज एक राजनीतिक दल के नेता विरोधी दल व उसके नेताओं पर आरोप लगाते रहते हैं। बदले में विरोधी भी आरोप लगाते हैं और राजनीति में आरोपों की लड़ाई चलती रहती है और ऐसा लगता है कि राजनीति के लोग कुछ कर रहे हैं। राजनीति में प्रतिस्पर्धी चलती रहती है कि तुम्हारी कमीज से मेरी कमीज ज्यादा सफेद है। दाग ज्यादातर राजनीतिक दलों के दामन में लगे रहते हैं लेकिन कोई अपने दामन के दाग नहीं देखा है, वह दूसरे के दामन को दागदार बनाता है और वहम में जीता है कि जनता उसको ज्यादा अच्छा राजनीतिक दल या नेता मानेगी और दूसरों को नकार देगी। राजनीतिक दलों के नेताओं को आरोप लगाने की आदत रहती है और वह इस आदत के कारण कभी कभी राजनीति के बाहर आरोप लगाते हैं उनको मुंह की खानी पड़ती है।

आप के संयोग केजरीवाल ने न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा पर आदत से मजबूर होकर आरोप लगा दिया कि वह आरएसएस के कार्यक्रमों में जाती हैं, उनके बच्चे सरकारी पैनल में वकील हैं। इसलिए वह उनके मामले में निष्पक्ष न्याय नहीं कर सकती। उन्की मांग थी उनके लगाए आरोपों के कारण न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा को उनके मामले से हट जाना चाहिए। उनको आशंका है कि वह उनके मामले में निष्पक्ष न्याय नहीं कर सकती। निचली अदालत से केजरीवाल को बरी कर दिए जाने पर सीबीआई ने ऊंची अदालत में अपील की और पहली सुनवाई में ही अदालत ने साफ कर दिया कि निचली अदालत ने जो फैसला दिया है, वह ठीक नहीं है और वह इसकी सुनवाई करेगी।

न्यायमूर्ति शर्मा ने कई मामलों में केजरीवाल के खिलाफ फैसला दिया है, इसलिए केजरीवाल का मामला उनकी अदालत में गया तो केजरीवाल को लगा कि हमेशा की तरह उनके मामले में फैसला उनके खिलाफ ही जाएगा। इसलिए उन्होंने न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा को उनके मामले से हटने की मांग की थी और याचिका दायर की थी। माना जाता है कि याची को अधिकार होता है कि वह जज बदलने की मांग करे और उसका कोई ठोस आधार बताये। केजरीवाल को भी अधिकार था लेकिन वह जज को उनके मामले से हटने के लिए कोई ठोस आधार पेश नहीं कर सके मजबूत उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, उन आरोपों के आधार पर जज को उनके मामले हट जाना चाहिए ऐसा वह चाहते थे। अगर ऐसा हो जाता तो एक मलत परंपरा होती क्योंकि फिर कोई भी जज पर आरोप लगाता और चाहता कि जज को उसके मामले को नहीं देखा चाहिए। यानी न्याय के लिए हर कोई फिर अपनी पसंद का जज चुनने लगता है।

इसी आधार पर न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने केजरीवाल की मांग पर हटने से इंकार कर दिया और केजरीवाल की जज को हटाने वाली याचिका का खारिज कर दिया। जस्टिस शर्मा ने दो टूक कहा कि वह केजरीवाल के मामले से उनके को अलग नहीं करेंगी। उनका कहना है कि नेता या वादी किसी जज की न्यायिक क्षमता को तय नहीं कर सकता। न ही वादी यह तय कर सकता है कि अदालत कैसे चले, न ही निराधार आरोपों पर जजों का चयन किया जा सकता है। जस्टिस शर्मा का कहना है कि जज का किसी मामले की सुनवाई से हटना कानून से तय होना चाहिए कि नहीं नैटिविटी से नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत आरोपों या सोशल मीडिया के दबाव के कारण जज का हटना न्यायिक स्वतंत्रता के लिए घातक है। जजों की क्षमता उच्च अदालत में तय करती है, पक्षकार नहीं।

उनका यह कहना सही है कि वह चाहती तो चुपचाप हट जाना उनके लिए अन्य जजों की तरह आसान रास्ता होता। पर जज की जगह की प्रतिष्ठा पर झुट्टे आरोप लगाकर रोज हमला किया जाए तो जज को न्याय व्यवस्था की बेहतरी के लिए जवाब देना ही होगा। अपनी बेटुटी शर्मा की होती है। उन्होंने अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में जाने के विषय में कहा कि ये कार्यक्रम राजनीतिक नहीं कानूनी थे। जजों व वकीलों के बीच कोर्ट के बाहर भी रिश्ता होता है किजरीवाल ने आरएसएस के कार्यक्रम के बारे में गड्डी थपे वह नहीं बताया मैं और कौन कीन से कार्यक्रम में गई थी। केजरीवाल की चपनलतक शैली से उनकी मंशा का पता चलता है। बच्चे सरकारी पैनल हैं इस पर जस्टिस शर्मा का कहना था कि सिर्फ इसी आधार पर जज की न्यायिक निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठाया नहीं जा सकता। नेताओं के बच्चे राजनीति में आते हैं, जजों के बच्चे वकालत करं तो उस पर कैसे सवाल उठाया जा सकता है।

रिश्तों से राजनीतिक छल अब चलेगा नहीं

प्रमोद जोशी

रिश्तों की राजनीतिक अभिलाषाएं आज उस सुधारस्था में नहीं हैं, जो नब्बे के दशक में थी। साफ है कि यह विवेक राजनीतिक गतिविधि मात्र थी। जिस तरह से बिल के गिरते ही पोस्टर छपकर आ गए, और राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन की योजना बन गई, वह बताता है कि बीजेपी इसकी तैयारी के साथ आई थी।

भारत में महिला आरक्षण को लेकर एक साथ कई सवाल हैं। पहला है कि संसद में संविधान संशोधन विधेयक पास नहीं हो पाया, या उसे पास कराने में किसी की दिलचस्पी नहीं थी? साफ है कि बीजेपी का झूठा इस मामले को उठाना, विरोधियों को उत्तेजित करना था, ताकि वे शोर मचाएं। भारतीय राजनीति विषयसंवीय नहीं है। सरकार जानती थी कि उसके साथ दो-तिहाई सदस्य नहीं हैं और आज के राजनीतिक हालात में उसे कई आशा नहीं करनी चाहिए थी कि विरोधी राजनीति का कोई हड़त उसके समर्थन में आता। तब फिर क्यों बिल पेश किया?

फोरीरी पर वह राजनीतिक तीर था, जो छद्मरी-शक्ति का लाभ उठाने के लिए चलाया गया था। संसद में जब बातें होती हैं, तब उन्हें गांव-गांव में सुना जाता है। विरोध में जितना शोर होगा, फायदा उठना ज्यादा होगा। उद्देश्य माहिल बनाना, नैटिविटी रचना या इसे जो भी कहें, उतना ही है कि विरोधियों की दिलचस्पी भी कम से कम महिला आरक्षण में नहीं थी। परिसीमन को लेकर भी उनके कई विचार थे। इससे ज्यादा उनका झूठा भी कुछ नहीं था। बहरहाल, इसका विपरीत-प्रभाव भी होगा, जो समूची राजनीति को अपनी चपेट में लेगा।

क्या महिलाओं को समझ में आ रहा है कि उन्हें छला जा रहा है? वह दीवार सवाल है कि इस विधेयक के पारित होने का लाभ बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव में मिलेगा या नहीं। असल बात यह है कि देश की राजनीति ने पिछले तीन दशक से नारी-शक्ति को छला है। उसे बहुत ज्यादा छला नहीं आ सकता। रिश्तों की राजनीतिक अभिलाषाएं आज उस सुधारस्था में नहीं हैं,



जो नब्बे के दशक में थीं। साफ है कि यह विधेयक राजनीतिक-गतिविधि मात्र थी। जिस तरह से बिल के गिरते ही पोस्टर छपकर आ गए, और राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन की योजना बन गई, वह बताता है कि बीजेपी इसकी तैयारी के साथ आई थी।

सबसे पहले एचडी देवेगौड़ा सरकार ने 81वें संविधान संशोधन विधेयक, 1996 के रूप में 12 सितंबर, 1996 को महिला आरक्षण विधेयक, पेश किया था। विधेयक पेश तो हुआ, लेकिन राजनीतिक आम सहमति न बनने और गठबंधन सरकार के भीतर विरोध के कारण इसे संयुक्त संसदीय समिति को पेजना पड़ा और 11वीं लोकसभा में ही पेश नहीं हो पाया।

सरकार ने इसबार जो विधेयक पेश किया था, वह संसदीय सौटी के परिसीमन पर केंद्रित था। उसके विरोधियों का कहना है कि परिसीमन देश को तोड़ देगा। वे कहते हैं कि 2023 के बिल को लागू करें। वर्ष 2023 के महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार, इसे परिसीमन के बगैर लागू नहीं किया जा सकता। यह कानून विशेष रूप से

जगनमोहन और परिसीमन के बाद ही लागू होने की शर्त से बंधा हुआ है। परिसीमन रहेगा तो आरक्षण भी रहेगा।

सरकार ने 2023 के बिल की अधिसूचना जारी कर दी है, ताकि वह लैप्स न हो। उसको प्रक्रिया ठीक से चली भी तो 2034 के चुनाव के पहले आरक्षण लागू नहीं हो सकेगा। संभव है कि 2039 में लागू हो। क्या महिलाएं इतना लंबा इंतजार करेंगी? दरअसल, देश की मुख्य-संचालित राजनीति देख रही पा रही है कि महिलाएं धीरे-धीरे बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभर कर आ रही हैं। यह ताकत अभी तक वोट के रूप में है, पर जल्द ही नेतृत्व के लेवल पर भी दिखाई पड़ेगा।

जब 2023 का वह बिल पास हो रहा था, तब उसे लेकर जबरदस्त सर्वानुमति थी। वह सर्वानुमति भी राजनीतिक-लाभ लेने तक की थी। उस वक भी सवाल था कि इसे फौरन लागू करने से रोका किसे ने? कांग्रेस के महिषाजुन खरगे ने राज्यसभा में कहा था, जब सरकार नोटबंदी जैसा फैसला ग़ुलत लागू कर सकती है, तब दिन महत्वपूर्ण विधेयक की याद सांके नही साल बाद क्यों आई? बात तो बहुत मार्क की कही थी, पर दस साल तक कांग्रेस की सरकार रही, वह

भी तो उसे लागू नहीं कर पाई। यूपीए के सहयोगी दल ही इसके लिए तैयार नहीं थे।

इंडिया ब्लाॉक के नेता आज कह रहे हैं कि हम उस विधेयक का समर्थन करेंगे जो 543 सीटों का वर्तमान संसद में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को तुरंत लागू कराए। उनका याचिका सरकार के साथ बैठकर इस विषय पर बात की? जब वे जानते हैं कि जगनमोहन और परिसीमन के बिना यह फिलहाल कानूनी रूप से संभव नहीं है, तो उन्हें ऐसी पेशकश का समर्थन करेगा, जिसके पीछे ईमानदारी हो और व्यवहारिकता भी।

व्यवहारिक बात है कि सांसदों की वर्तमान संख्या को देखते हुए, किसी पार्टी को संसद इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा। लोकसभा में मोटे तौर पर 86 प्रतिशत पुरुष हैं और देश की विधानसभाओं में करीब 90 प्रतिशत। इसी संख्या पर आरक्षण लागू हुआ, तो बड़ी संख्या में पुरुषों का पता साफ हो जाएगा। [संई नहीं चाहेंगे कि उसका चुनाव-क्षेत्र आरक्षण के दायरे में चला जाए।] खुले ही एक-तिहाई सीटें महिलाओं के कोटे में जाएंगी, पर किन्हीं का खिन्ना, पता नहीं। एक-एक चुनाव क्षेत्र को तैयार करने में बरसों की मेहनत और लाखों की रकम खर्च होती है। यह सच उन्हें मंजूर होता, तो 1996

से अब तक यह सच रुका हुआ क्यों है? बहरहाल, पुरुषों की इस राजनीतिक को महिलाओं की बढ़ती ताकत ही डिकाने लगाएगी। अभी तक माना जाता था कि महिलाओं की राजनीतिक आवाज नहीं होती है। वोट के रूप में उनकी आवाज को मान्यता मिल चुकी है। कौन-सा राज्य है, जहां पार्टियां महिलाओं को लिए चुनावी कार्यक्रम लेकर नहीं आ रही हैं। ये कार्यक्रम वोट के रूप में हैं।

दूसरी तरफ राजनीतिक कार्यक्रमों को के रूप में भी महिलाओं के बीच खामोशी क्रांति हो रही है। इसकी शुरुआत स्थानीय निकायों, यानी पंचायतों और नगरपालिकाओं में, महिलाओं को न्यूनतम 33 प्रतिशत आंशिकता के लिए करने से हुई है, जो 1993 के 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के तहत उन्हें प्राप्त हुआ है। इस आरक्षण को बिहार, उत्तराखंड, महाराष्ट्र सहित 20 से अधिक राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों ने बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। जमीनी स्तर पर अब कविता साहेबदास साहब से अधिक महिलाएं जन-प्रतिनिधि के रूप में काम कर रही हैं, जो उन निकायों के कुल सदस्यों का करीब 46 प्रतिशत हैं। [उन्होंने से कुछ अपवाद हैं, भादवी और वेस्टो के लिए आइड का काम कर रही हैं, पर ज्यादा बड़ी संख्या उन महिलाओं की है, जो ने केवल सचिव हैं, बल्कि अपनी कुशलता साबित कर रही हैं।]

इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी मज्म ले रही हैं। ग्राम सभा की सदस्य, जिला स्तर पर जाना चाहती हैं, नगरपालिका की पाबंद विधायक और उम्मेदर ऊपर के स्तर पर उनकी संख्या बढ़ रही है, क्योंकि एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी भी सामने आ रही है। स्थानीय निकायों के कुल सदस्यों में 46 प्रतिशत महिलाएं हैं, वहीं लोकसभा और विधानसभाओं में वह प्रतिशत काफी कम है। 18वीं लोकसभा में 543 में से 75 महिला सांसद (लगभग 14 प्रतिशत) हैं, जो 2024 में चुनाव बटुकर आई हैं। राज्यसभा में लगभग 39 (17 प्रतिशत) महिला सदस्य हैं। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार, 4,666 सांसदों/विधायकों में से केवल 464 यानी 10 प्रतिशत महिलाएं हैं। यह असंतोष है, जिसे अब महिलाएं ही आगे बढ़कर दूर करेंगी।

मुकाबले की रणनीति बने : किसानों और कृषि के सामने मानसून का जोखिम

डॉ. जयंती तालभट्टारी

भारतीय मौसम विभाग ने अल नौ की के कारण 2026 में सामान्य से कम मौसमसून का अनुमान लगाया है। यह पूर्वानुमान पिछले 26 वर्षों में मानसून का सबसे कम शुरुआती अनुमान है। इससे देश में कृषि उत्पादन और खाद्य कीमतों पर असर पड़ सकता है।

हाल ही में विश्व बैंक ने कहा है कि वर्ष 2026 में कमजोर मानसून से भारत में कृषि की पैदावार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है। इससे महंगाई बढ़ने और विकास दर में कमी की चुनौती होगी। भारतीय मौसम विभाग ने अल नौ की के कारण 2026 में सामान्य से कम मौसमसून का अनुमान लगाया है। यह पूर्वानुमान पिछले 26 वर्षों में मानसून का सबसे कम शुरुआती अनुमान है। इससे देश में कृषि उत्पादन और खाद्य कीमतों पर असर पड़ सकता है। मौसम विभाग ने बारिश के दीर्घकालिक औसत (एलपीई) के 92 प्रतिशत रहने की संभावना बताई है। यह पूर्वानुमान 5 फीसदी अधिक या कम की मॉडल त्रुटि के साथ जारी किया गया है। फ्राईडेट की रिपोर्ट के अनुसार देश में 75 फ्राईडेट वर्ष पर आधारित मौसमसून सीमा में 5 प्रतिशत कम-ज्यादा के साथ 94 प्रतिशत वर्षा हो सकती है।

पिछले आंकड़े बताते हैं कि सामान्य से



कम मौसमसून वाले वर्षों में जब बारिश का समय, वितरण और फैलाव लगभग समान रहा तब खरीफ के उत्पादन में अधिक कमी नहीं हुई किन्तु गैर-सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाने वाली दलहन-तिहान फसलों के लिए जोखिम हो सकती है। पश्चिम एशिया संघर्ष से महंगे उर्वरक, महंगे तेल और आपूर्ति शृंखला बाधित होने से खेती को लागत बढ़ी है, तब कमजोर मानसून से न केवल कृषि, वरन अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर हो सकता है। पेयजल समस्या बढ़ सकती है।

नीति आयोग के मुताबिक देश के कुल फसल रकबे का केवल 55 फीसदी सिंचित है और 45 प्रतिशत खेती मौसमसून

पर निर्भर है। सीडब्ल्यूएमआई के अनुसार, लगभग 74 प्रतिशत क्षेत्र पर 65 प्रतिशत चावल की खेती वाले क्षेत्र पहले से ही भारी जल-संकट का सामना कर रहे हैं। व्यावसायिक फसलों और औद्योगिकीकरण की बढ़ते रूढ़िवाद से भारत में मौसमसून की वर्षा पर निर्भरता बढ़ी है। अब अल-नौ की खरों और कमजोर मौसमसून की आशंका से जलवायु के सुखने और खेती के लिए पानी की कमी की चिंता बढ़ गई है। केंद्रीय जल आयोग देश में कुल 183.565 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) क्षमता वाले 166 प्रमुख जलवायु के भंडारण पर नजर रखता है। इस समय इन जलवायु में करीब 100

44.71 प्रतिशत है। हाल में इसमें तेजी से कमी आई है।

वर्ष 2024-25 में भारत में 35.70 करोड़ टन खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। इस वर्ष 2025-26 में इससे भी अधिक खाद्यान्न उत्पादन की संभावना है। 2026 में गेहूं की खेती का रकबा भी पिछले वर्ष के 328.04 लाख हेक्टेयर की तुलना में बढ़कर लगभग 334.17 लाख हेक्टेयर हो गया है। ये एक और अच्छी फसल की संभावना का संकेत देता है। एफसीआई के पास केंद्रीय पूल में एक अप्रैल 2026 को लगभग 6 लाख मीट्रिक टन 600 लाख टन से अधिक का उपलब्ध स्टॉक खाद्य सुरक्षा के मामले में भारत को मजबूती है। इस समय देश के 80 करोड़ से अधिक कमजोर वर्ग के लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि हाल ही में प्राकृतिक निर्यात आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने 55 अरब डॉलर मूल्य का कृषि निर्यात किया है और भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कृषि निर्यात के लिए देश के कृषि निर्यात परिदृश्य है वह उपकर दिखाई दे रहा है कि वर्ष 2014 से 2025 के बीच प्रमुखतः खाद्य उत्पादन का निर्यात वार, गुना, फलों और दालों का निर्यात तीन गुना, खाद्यान्न का निर्यात दो गुना और चावल के निर्यात में करीब 62 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

भारत सरकार ने चर्चले बाजारों की स्थिर करने और उत्पादकों को लाभकारी प्रतिलिपि सुनिश्चित करने के लिए प्रतिनिधिक और किसानों के केंद्रित कदम उठाते हुए 50 लाख मीट्रिक टन गेहूं और अतिरिक्त 10 लाख मीट्रिक टन गेहूं उत्पादित के निर्यात को मंजूरी दे दी है। लेकिन कमजोर मानसून के चलते आगामी निर्यात आदेशों की पूर्ति के लिए संजनात रखी जाए। देश ने देखा है कि वर्ष 2021-22 में 70 लाख टन से अधिक गेहूं का निर्यात किया था, लेकिन वर्ष 2024 में गेहूं का आयात कर 60 लाख टन। निर्यात, कम बारिश से जलवायु में पानी का स्तर गिरने से सिंचाई और पंपों के पानी की उपलब्धता प्रभावित होगी, ऐसे में अभी से जल संरक्षण के प्रयास शुरू होने चाहिए। इस समय जो खुदाय महंगा हो रहा 3.40 प्रतिशत है, उसके बढने की आशंका है। अंतर्राष्ट्रीय की रोकथाम की रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा।

भारत को फसल विविधीकरण और खेती में आधुनिक तकनीक के एकीकरण के साथ आगे बढ़ना होगा। सिंचाई व्यवस्था की नई नीति तैयार करना लाभदायक होगा। अनाज बर्बाद होने से बचाने के लिए देश में वर्ष 2028 तक सरकारी भंडार में 700 लाख टन अनाज भंडारण की नई क्षमता विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना को तेजी से आगे बढ़ाया जाना होगा।

बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशी राम की विरासत हासिल करने की जुगत

जितोक्त

राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि यदि कांग्रेस ने पहले बेहतर काम किया होता तो कांशी राम को अलग से संघर्ष नहीं की आवश्यकता नहीं पड़ती। उन्होंने स्वीकार किया कि कांग्रेस की पूर्व की कुछ कमियां थीं जिनके कारण कांशी राम को अलग से संघर्ष करना पड़ा।

पिछले दिनों लोकसभा में विषय के नेता राहुल गांधी ने बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशी राम को सामाजिक न्याय का योद्धा और शराबिधारी का प्रतीक बताते हुए उन्हें मरणोपरान्त भारत वर दिए जाने की मांग की। इस आशंका का एक पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखकर उन्हें सम्मानित करने के लिए कहा। यह बात राहुल गांधी ने लखनऊ में 15 मार्च, 2026 को कांशी राम के जन्मदिन पर उन्हें ब्रह्मजाल देते हुए की। राहुल गांधी ने उनकी विचारधारा का जमावत की और कांग्रेस की पिछली गलतियों को स्वीकार करते हुए उनके संघर्ष की याद किया। उनका भी नहीं राहुल गांधी ने कांशी राम को एक ऐसे नेता के तौर पर स्मरण किया जिन्होंने दलितों और हाशिये पर पड़े समुदायों के लिए अपने जीवन में कभी समझौता नहीं किया। यहां तक तो ठीक है लेकिन राहुल गांधी ने यह कहकर कि अगर नरेंद्र जी जीवित होते तो कांशी राम कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने, उनके कद को छोट करके का प्रयास किया है।

उपर दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने राहुल गांधी के इस कदम को दलित वोट बैंक में सेंथ लगाने की कोशिश बताते हुए उनकी कड़ी आलोचना की और कहा कि कांग्रेस ने सता में रहते हुए कांशी राम का सम्मान नहीं किया। इस कदम को 2027 के उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव पर फलित मतदाताओं की कांग्रेस को और आकर्षित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस इस कदम के जरिये दलित वोट बैंक को फिर से अपने पाल में लाने की कोशिश कर रही है। मायावती ने बहुत कि जबरन का निधन हुआ था तब कांग्रेस ने एक दिन का शोक तक नहीं मनाया था और वह अब किस मुंह से उन्हें भारत



रख देने की मांग कर रही है। मायावती ने राहुल गांधी के इस कदम को दलितों के प्रति कांशी राम को दिखावा बताया और कांशी राम की विरासत को हाथियाता का प्रयास कर दिया।

राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि यदि कांग्रेस ने पहले बेहतर काम किया होता तो कांशी राम को अलग से संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उन्होंने स्वीकार किया कि कांग्रेस की पूर्व की कुछ कमियां थीं जिनके कारण कांशी राम को अलग से संघर्ष करना पड़ा। राहुल गांधी आज स्वीकार करते हैं कि वह कांशी राम के विचारों और सिद्धांतों को सही मायने में समझते हैं और सीसीएल वह लोकसभा के भीतर और बाहर भी दलितों, शोषितों, आदिवासीयों, अल्प पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्गों के अधिकारों जैव मुद्दे खूब उठाते रहते हैं।

संभव है वह यह साबित करना चाहते हों कि कांशी राम के विचारों और सिद्धांतों को सही मायने में वही समझते हैं और इन वर्गों को बदतरलों का मुखा उठाते रहते हैं। राहुल गांधी का यह मानना है कि वह बरखा को हड़पने का कोई झरना नहीं रखते बल्कि कांशी राम की सोच और विचारधारा का विस्तार कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा के नतीजे इसका स्पष्ट संकेत देते हैं। दलितों, शोषितों और पिछड़ा वर्ग ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी

गठबंधन को तरजीह दी थी। जिसके चलते बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। कभी बरखा के लोकसभा में 14 संसद थे। यह बात 1999 की है, तब बरखा के सुप्रीमो कांशी राम थे।

कांशी राम से मेरी बसियों मुलकत है। उनके जुनून को मैंने नजदीक से देखा है। उन्हें दिल्ली के रेहगुपु (कल्लुवा के पास) एक छोटे से कमरे में भी देखा है और हमपुर् गेड वाले सांसदों के बंगले में देखा। उनके रहन-सहन में कोई फर्क नहीं दिखता। वह जैसे सीता-साथे, साफगोई इसान पहले थे, यहां भी वैसे ही दिखे। फिर कांशी राम को 1971 में इंडिया भारतीय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचितों के शक्ति संस्था से बने संगठन बामसेफ, 1981 में दलित, शोषित समाज संघर्ष समिति (डीएसए) के निर्माण करते देखा, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी संस्थाएं न तो धार्मिक हैं और न ही राजनीतिक और न ही हमारा उद्देश्य आंदोलन करना है बल्कि हमारा यह सामाजिक संघटन है। उस समय उपाध्यका नारा था—ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया छोड़, बाकी सब छोड़। इसके माध्यम से दलितों, शोषितों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के बीच चेतना जागई और उनकी संख्यात से अगर जगह छिदरे मतों का एकीकरण करने का काम किया। अजीब तक ये सभी मत वोट भाव से कांग्रेस तथा अन्य पार्टियों के बीच विभाजित हो जाया करते थे।

लिहाजा 1984 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी (बरसा) की स्थापना की और नारा दिया जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी। 1984 में निर्मित बरसा के संस्थापक कांशी राम छलीगढ़ के जॉर्जरी से लोकसभा के चुनावी मैदान में कूदे और हार गए। 1988 और 1989 का चुनाव हारने के बाद कांशी राम ने कहा था कि बरसा पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा नजर में आने के लिए और तीसरा जीत दर्ज करने के लिए लड़ती है। कांशी राम 1991 में इटाला और 1996 में बोलियापुर से लोकसभा के चुनाव जीतें और 1998-2004 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। इन चुनाव परिणामों से राजनीति में बरसा को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो गया। अब पार्टी के लोग कांशी राम को मान्यवर, साहब कांशी राम, बहुजन नायक कांशी राम आदि से

संबोधित करने लगे थे। इसी प्रकार मायावती ने 1989 में बिजनौर से भारी मतों से लोकसभा का चुनाव जीत कर बरसा की धाक जमा दी। लेकिन कांशी राम ने मायावती का कार्य क्षेत्र उत्तरप्रदेश को ही सीमित रखा। लिहाजा 1995 में उन्होंने उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाला और वह चार बार राज्य की मुख्यमंत्री रहें 1995, 1997, 2002-2003 तथा 2007-2012 तक। पहली तीन बार वह भाजपा के विरोध में मुख्यमंत्री रहें जिन्होंने 2007-2012 तक शुद्ध बरसा की बदौलत। तीन बार सांसद होने के बावजूद कांशी राम का मन संसद में नहीं रमता था और संसद के तौर पर उनका योगदान अधिक नहीं रहा। उन्होंने मुझे बहुत ही बेवकाल से बताया था कि वहां बैठकर वह जाया करने से बेहतर है पार्टी संघटन को मजबूत करना। कांशी राम अक्सर कहते थे कि हम लोग देश को आबादी को 70 फीसदी से ज्यादा है। हमारा शोषण ये तथाकथित बड़ी पार्टियां कई दशकों से करती आ रही है। उन्होंने खिलाफ हमारी लड़ाई है।

वे कहते थे मैं अपने हक की अरख जागूये रखने के लिए उत्तर से पश्चिम तथा पूरव से पश्चिम चलाकर लिगाना रहता हूं। देशक उनके जुनून और धर्म ने बरसा को मजबूत कर दिया लेकिन उनकी संसद की कामना पर। उन्होंने सितम्बर, 2003 को पार्टी की बागडोर मायावती को सौंप दी। 19 अक्टूबर, 2006 को 72 साल की उम्र में कांशी राम का निधन हो गया। कांशी राम के निधन के बाद बरसा में एकजुटता का अभाव ही दिखाई दिया। 2019 में उत्तरप्रदेश विधानसभा में 19.3 प्रतिशत मत प्राप्त कर दूसरी बड़ी पार्टी थी जनक 2022 में हिंसक कर चौथे स्थान पर आ गयी और उसके मतों की संख्या सिक्कुर कर 12.88 फीसदी रह गयी। 2007 में विधानसभा में 206 सीटें थीं जो 2012 में घटकर 80 रह गयी। उसके बाद तो बरसा मतमोखी ही होती चली गयी। 2017 में उसकी 19 सीटें थीं जो 2022 में मात्र एक उमाशंकर सिंह के रूप में। चुनौती विवेक जयन के दिवंगन उसकी कमजोरी होती कड़ी का लोग कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुद उठा रहे हैं। वे आज की राजनीति में कांशी राम का किस्म बनने की कोशिश कर रहे हैं तो इसकी वजह वर्तमान बरसा नेतृत्व को खोजनी होगी।

गंगरेल बांध के उन्नयन को मिली रफ्तार, 65.5 करोड़ से बढ़ेगी बांध की उम्र

डैम सेफ्टी पर फोकस, मरम्मत व संधारण कार्यों को हरी झंडी

नई दृष्टिविडु / धर्मतरी

जिले में स्थित रविशंकर सागर जलाशय, जिसे गंगरेल बांध के नाम से जाना जाता है, को अब उन्नयन और महत्वपूर्ण मरम्मत कार्यों के जरिए और अधिक सुदृढ़ व सुरक्षित बनाया जाएगा। राज्य शासन ने बांध की दीर्घकालिक सुरक्षा और संरचनात्मक मजबूती के लिए 65.5 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। इस पहल से न केवल बांध की आयु में वृद्धि होगी, बल्कि डैम सेफ्टी के मानकों को भी नई मजबूती मिलेगी।

प्रस्तावित कार्यों के अंतर्गत वर्टिकल प्रेशर ड्रेन

की सफाई सहित अन्य आवश्यक संधारण कार्य किए जाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इन आधुनिक तकनीकों के उपयोग से बांध की आंतरिक संरचना सुदृढ़ होगी और जल रिसाव की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकेगा। कलेक्टर ने इस परियोजना को प्राथमिकता देते हुए संबंधित अधिकारियों को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने टेंडर प्रक्रिया में तेजी लाने, गुणवत्ता मानकों के कड़ाई से पालन और कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 1978 में निर्मित यह बहुउद्देशीय जलाशय पिछले लगभग चार दशकों



से अधिक समय से क्षेत्र की जीवनरेखा बना हुआ है। गंगरेल बांध के माध्यम से नहरों द्वारा धमतीर सहित कई जिलों में हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई की जाती है। इसके साथ ही यह जलाशय

पेयजल आपूर्ति, औद्योगिक उपयोग और 11.2 मेगावाट विद्युत उत्पादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कलेक्टर ने कहा, रविशंकर सागर जलाशय केवल धमतीर ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की जीवनरेखा है। इसकी सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्वीकृत तम से बांध की संरचनात्मक मजबूती सुनिश्चित होगी और सीपेज की समस्या का वैज्ञानिक समाधान किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सतत मॉनिटरिंग, गुणवत्ता परीक्षण और समयबद्ध कार्य योजना तैयार की गई है।

खास खबर

अवैध ईट भट्टे पर बड़ी कार्रवाई, लाखों ईंटें और लकड़ी जप्त



नई दृष्टिविडु / राजनांदगांव

जिले में राजस्व एवं वन विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम माहुलखोपड़ी में संचालित एक अवैध ईट भट्टे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों की संख्या में ईंटें, लकड़ी एवं अन्य सामग्री जप्त की है। बिना किसी वैध अनुमति एवं दस्तावेज के संचालित इस भट्टे से लगभग 3 लाख 20 हजार पक्की ईंटें, 1 लाख 60 हजार कच्ची ईंटें, 70 टॉन्स मिट्टी तथा 6 टॉन्स लकड़ी जप्त की गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार डोंगरगांव विकासखण्ड के ग्राम माहुलखोपड़ी में टाटा बाई की भूमि पर दाऊ लाल द्वारा अवैध रूप से ईट निर्माण कार्य किया जा रहा था। मामले को जानकारी मिलने पर कलेक्टर के निर्देशन में संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई आगे भी सुर्पाण गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से बंद कराया।

कार्रवाईके दौरान जप्त की गई लकड़ी को सुरक्षाार्थ वन विभाग के सुपुर्द किया गया है, वहीं अन्य सामग्री को अग्रिम कार्रवाई तक ग्राम पंचायत गिरगांव के सुपुर्द किया गया है। इस कार्रवाई में नवाना तहसीलदार चिराग रामटेके, जेन ऑफिसर आकाश ठाकुर सहित राजस्व एवं वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध गतिविधियों के विरुद्ध इसी प्रकार सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

संघर्ष से समृद्धि तक के सफर की मिसाल, बिहान मिशन से जुड़कर बदली जिंदगी



गौरिला-पेण्डु-मरवाही। सीमित संसाधनों और आर्थिक तंगी के बीच जीविक पान करने वाली गौरिला-पेण्डु-मरवाही जिले की सोकोला तहसील के ग्राम पंचायत मड़ई की सुती ओमपती आज ग्रामीण महिला सशक्तिकरण की सफर मिसाल बन गई हैं। अपने आत्मनिर्भरता, मेहनत की बदौलत उन्होंने न केवल अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया, बल्कि समाज में एक नई पहचान भी स्थापित की है।

ओमपती के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन तब आया, जब वे छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान से जुड़ीं। इस मिशन ने उन्हें स्वयंजगार के अवसर उपलब्ध कराए, साथ ही आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और प्रोत्साहन भी दिया। जिले की जलाशो व्यवसायता समूह की सक्रिय सदस्य के रूप में ओमपती ने समूह की अन्य महिलाओं के साथ मिलकर लघु उद्यमों की शुरुआत की। प्रारंभिक चरण में उन्होंने महुआ लड्डू, नारियल लड्डू एवं मशरूम उत्पादन जैसे व्यवसाय अपनाए। उनकी मेहनत और उन्मादी की गुणवत्ता के चलते स्थानीय बाजारों में इनकी मांग लगातार बढ़ती गई।

वर्तमान में ओमपती प्रतिमाह 8 से 10 हजार रुपये तक की आय अर्जित कर रही हैं, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वे अब न केवल आत्मनिर्भर बन चुकी हैं, बल्कि लक्ष्मिपति दीदी बनने की ओर अग्रसर हैं। ओमपती की सफलता उस बात का प्रमाण है कि यदि सही दिशा, सफर में और दृढ़ संकल्प मिले, तो कोई भी महिला अपने जीवन की दिशा बदल सकती है। आज वे अपने परिवार के लिए सफर बनने के साथ-साथ गांव की अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनी हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही हैं।

नई दृष्टिविडु / सरगुजा

छत्तीसगढ़ शासन की लोक-कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण की नई दिशा मिल रही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) और बिहान के समन्वय से महिलाएं स्वरोजगार के नए अवसर प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। इसी क्रम में सरगुजा जिले के रिमा स्व-सहायता समूह की सदस्य श्रीमती सविता ने अपनी मेहनत और योजनाओं के बेहतर उपयोग से आर्थिक समृद्धि की प्रेरक मिसाल प्रस्तुत की है।

डबरी निर्माण से खुला आस का रास्ता

श्रीमती सविता ने बताया कि दो वर्ष पूर्व उन्होंने मनरेगा के अंतर्गत अपने खेत में डबरी का निर्माण कराया था।

मिला संबल, बढ़ी आय

स्व-सहायता समूह से जुड़ने के बाद उन्हें आर्थिक सहयोग मिला। उन्होंने

श्री रामलला दर्शन योजना से श्रद्धालुओं को मिला आरस्था का अवसर



नई दृष्टिविडु / जशपुर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित श्री रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत जशपुर जिले के श्रद्धालुओं को अर्थव्यय पान में प्रभु श्रीराम के दर्शन का अवसर निरंतर प्राप्त हो रहा

है। योजना के तहत अब तक जशपुर जिले से 2640 श्रद्धालु अयोध्या घुम पहुंचकर श्री रामलला के दर्शन कर चुके हैं, जिससे क्षेत्र में धार्मिक उत्साह का वातावरण बना हुआ है। इसी क्रम में मंगलवार को योजना के तहत 13वें ज्येष्ठ को विभिन्न जनपद पंचायतों एवं

गया। इसके अतिरिक्त पथलालां जनपद पंचायत से भी श्रद्धालुओं का जत्था अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। योजना के माध्यम से शासन द्वारा श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं में उत्साह है।

पीएम आवास योजना से स्वयं के पक्के मकान का सपना हुआ साकार

ग्राम लालाकापा के प्रभा को मिला सुरक्षित, मजबूत पक्का मकान

नई दृष्टिविडु / मुंगेली

जीवन में हर व्यक्ति के मन में एक सपना होता है कि उसका खुद का एक आशियाना हो, जिसमें वह चैन की नींद ले सके। प्रधानमंत्री आवास योजना से आम लोगों के पक्के आवास का सपना पूरा हो रहा है, जिससे उन्हें उनके सपनों का आशियाना मिल रहा है। इसी कड़ी में मुंगेली विकासखण्ड के ग्राम लालाकापा के निवासी प्रभा के पक्के मकान का सपना साकार हुआ है। उन्होंने सुरक्षित और मजबूत पक्का मकान मिला है। प्रभा ने बताया कि उनके पास पहले खुद का पक्का घर नहीं था। वह एक जरूरत कच्ची झोपड़ी में रहते थे, जहां बारिश में पानी टपकता और सर्दियों में ठंड से बचना मुश्किल हो जाता था। गांव में जब गरीब परिवारों को



आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकारी योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई, तब प्रभा ने भी उम्मीद के साथ आवेदन किया। उनकी वास्तविक स्थिति को देखते हुए उनका चयन हो गया। कुछ समय बाद शासन की ओर से उन्हें

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 01 लाख 20 हजार रुपये की स्वीकृति मिली। इस सहयता से प्रभा का वर्षों पुराना सपना साकार हुआ और उन्हें सुरक्षित, मजबूत पक्का घर मिल गया। अब उनके पास ऐसा आशियाना है,

जहां वे अपने परिवार के साथ सम्मान और सुरक्षा के साथ जीवन जी रहे हैं। नया घर मिलने के बाद प्रभा का आत्मविश्वास और भी मजबूत हुआ है। उन्होंने इस योजना के संस्लान के लिए शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया है।





हाल ही में एक अवॉर्ड शो में एक जाने – माने स्टैंड-अप कॉमेडियन ने अपने ‘बुरबुर’ जैसा एक से इंडस्ट्री की भीमारी बीबीया पर तंज किया। फिल्ले ने भी इंडस्ट्री में टॉपिक्स सिटी को लेकर खुद बसस वला। अनुसंग कथस्थ जेठे निदेशक तो मुबई से शिपट ही हो गए। इस मुड़े पर विमय कहते हैं, ‘मुझे लगता है अनसर्टाईनटी है, डर है कि क्या चलेगा क्या नहीं क्योंकि स्टैबल बड़ पर है’ मुझे याद है एक समान में तीन-चार करोड़ पर मैं सीता बजट फिल्म बन जाती थी। आज की तारीख में मैं जब प्रोड्यूसर से बात करता हूँ, तो उन्हें बजट की फिल्लरी की बात 15-20 करोड़ तक बता देती है। अब इसमें मार्केटिंग और पीपुल को जोड़ दिया जाता है, तो फिल्म का बजट 30-35 करोड़ तक चला जाता है। आज फिल्म निर्माण का गणित अनसर्टेन से बदल गया है। उन हिस्सों से कुछ कॉन्सिडर पेसे है नहीं, जिन पर इतना खर्च किया जाए, पर करना पड़ रहा है। कुछ सजेक्ट्स पेसे हैं, जिन पर काफी खर्च करना पड़ेगा, मगर उनकी रिकवरी की गारंटी नहीं है। इन मुद्दों का कारण अनिश्चितता बड़ जाती है।’



कवर्धा एसपी ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा की अलख जगाने वाले शिक्षकों का किया सम्मान

नई दृष्टिबिंदु / कवर्धा

कबीरधाम जिले में नक्सल प्रभावित ग्रामों के बच्चों और युवाओं को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शिक्षकों को आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सम्मानित किया गया। पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह द्वारा इन शिक्षकों को शॉल भेंटकर उनका अभिनंदन किया गया। यह सम्मान उन शिक्षकों को दिया गया, जो सामुदायिक पुलिसिंग के अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों को निरंतर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और उन्हें उच्चल भविष्य की ओर अग्रसर कर रहे हैं। इन शिक्षकों के प्रयासों से अनेक बच्चे एवं युवा शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़े हैं।

उल्लेखनीय है कि उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा के हृद्द संकल्प एवं प्रभावी नीतियों के परिणामस्वरूप

कबीरधाम जिला आज नक्सल मुक्त हो चुका है। इस उपलब्धि में पुलिस के साथ-साथ इन शिक्षकों का भी सराहनीय योगदान रहा है।

पुलिस अधीक्षक सिंह ने कहा कि वनांचल क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार ही स्थायी शांति और विकास का सबसे मजबूत आधार है। इन शिक्षकों ने कठिन परिस्थितियों में भी बच्चों और युवाओं को शिक्षा से जोड़ने का जो कार्य किया है, वह अत्यंत सराहनीय है। कबीरधाम पुलिस आगे भी ऐसे प्रयासों को प्रोत्साहित करती रहेगी, जिससे हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार और बेहतर भविष्य मिल सके। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र सिंह बघेल, अमित पटेल, कवर्धा एसडीओपी आशोष शुक्ला, निरीक्षक नितिन तिवारी, प्रधान आरक्षक चनाराम सिंह, चंद्रशेखर शर्मा (पत्रकार), मनीष मिश्रा (पत्रकार) सहित उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कमचारियों ने शिक्षकों के



योगदान की सराहना करते हुए उनके उच्चल भविष्य की कामना की।

कबीरधाम पुलिस द्वारा सामुदायिक पुलिसिंग के तहत नक्सल प्रभावित ग्रामों में स्कूलों का संचालन किया जा रहा है, जहाँ बच्चों को पढ़ाई का पूरा खर्च भी पुलिस विभाग द्वारा वहन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, वनांचल क्षेत्रों में पढ़ाई छोड़ चुके युवाओं को पुनः शिक्षा एवं रोजगार से जोड़ने हेतु विशेष पहल की गई है। पुलिस विभाग द्वारा ऐसे युवाओं के लिए ओपन स्कूल परीक्षा के फार्म स्वयं के व्यय से भरवाए गए तथा उन्हें परीक्षा केन्द्र तक पहुंचाने के लिए वाहन सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। इन शिक्षकों ने युवाओं को कौशल प्रदान कर उन्हें परीक्षा के लिए तैयार किया, जिसके परिणामस्वरूप कई युवा ओपन परीक्षा उत्तीर्ण कर आज विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी प्राप्त कर अपने जीवन को संवार रहे हैं।

खास खबर

कलेक्ट्रेट में 'आम की लूट' ! काम ठप, कर्मचारी मस्ती में—बांस-चादर लेकर पेड़ों पर धावा, अफसर साइलेंट; सिस्टम पर उठे सवाल

नई दृष्टिबिंदु / अंबिकापुर



जिले के कलेक्ट्रेट परिसर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसने सरकारी कामकाज की हकीकत पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां आमजन अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दफ्तरों के चक्कर काटते हैं, वहीं यहां कर्मचारी सरकारी काम छोड़कर आम तोड़ने में मशगूल नजर आए।

मंगलवार शाम करीब 4 बजे का यह मामला है, जब दफ्तरों में फाइलों का निपटारा होना चाहिए था, उस समय कलेक्ट्रेट परिसर में आम तोड़ का निगटारा चल रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (आरईएस) विभाग के अधिकारी-कर्मचारी बांस लेकर पेड़ों पर आम गिरा रहे थे, जबकि नीचे खड़े कर्मचारी चादर फैलाकर उन्हें इकट्ठा कर रहे थे। इस दौरान दफ्तरों का कामकाज लगभग ठप रहा और अपने काम से हटते-हटते लोगो इधर-उधर भटकते नजर आए। सरकारी परिसर में इस तरह की गतिविधि न सिर्फ लापरवाही, बल्कि खुलेआम अनुशासनात्मकता का उदाहरण बन गई।

सबसे चौकाने वाली बात यह रही कि मौके पर मौजूद जिम्मेदार अधिकारी पूरे घटनाक्रम के दौरान मुकदर्शक बने रहें। न किसी को रोका गया, न ही कोई कार्रवाई की गई। इससे साफ संकेत मिलता है कि विभागिय नियंत्रण और जवाबदेही किस हद तक कमजोर हो चुकी है।

कलेक्ट्रेट जैसे संवेदनशील प्रशासनिक केन्द्र में इस तरह का नजारा सामने आना कार्यसंकुचित पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। जिन कमचारियों पर जनता की समस्याएं सुलझाने की जिम्मेदारी है, वे खुद निजी गतिविधियों में उलझे दिखे—यह स्थिति आमजन के भरोसे को झटका देने वाली है। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों में नाराजगी साफ देखी जा रही है। नागरिकों ने दोषी कर्मचारियों और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

अफसर का गोलमोल जवाब

मामले में जब कार्यपालन अभियंता अविनाश मिश्र से पक्ष जानने की कोशिश की गई, तो उन्होंने खुद को बाहर बजाते हुए कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया और काँट काट दी। उनका यह रवैया भी सवालियों के घेरे में है।

बड़ा सवाल

क्या सरकारी दफ्तर अब काम के बजाय आराम की जगह बनते जा रहे हैं? क्या जवाबदेही सिर्फ कागजी तक सीमित रह गई है? यह घटना सिर्फ आम तोड़ों की नहीं, बल्कि सिस्टम में घुस चुकी लापरवाही की एक तस्वीर है—जिसका जवाब अब प्रशासन को देना होगा।



जीवनदीप कार्यकारिणी समिति की बैठक में स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर

नई दृष्टिबिंदु / बेमतरा

कलेक्टर एवं जीवनदीप कार्यकारिणी समिति की अध्यक्ष सती प्रतीति ममगाई की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला अस्पताल स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में जीवनदीप कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में आम नागरिकों को बेहतर एवं सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर ने कहा कि जिला अस्पताल का संचालन बेहतर ढंग से हो तथा मरीजों को गुणवत्तापूर्ण उपचार मिल सके, इसके लिए सभी आवश्यक पहलुओं पर निगरानी की जाएगी। उन्होंने चिकित्सकीय स्टाफ, एवं डॉक्टरों को मरीजों के साथ संतुलित एवं संवेदनशील व्यवहार रखने के निर्देश दिए।

बैठक में अस्पताल में कमचारियों की भोजन व्यवस्था, पावर बैकअप को उपलब्धता, मानव संसाधन की पूर्ति, परिसर में पार्किंग व्यवस्था, ड्रेनेज

किशोरी बालिकाओं और महिलाओं की स्वास्थ्य पर रखें नजर—कलेक्टर ममगाई विभागीय योजनाओं का करें प्रभावी क्रियान्वयन

नई दृष्टिबिंदु / बेमतरा

कलेक्टर प्रतीति ममगाई ने जिला कार्यालय के सभाक्ष दिशा भवन में महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक लेकर विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन एवं धरातल स्थल पर भौतिक स्थिति की समीक्षा की। कलेक्टर ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि महिलाएं एवं बच्चे समाज के अभिन्न हिस्सा हैं। इनके स्वास्थ्य पोषण, टीकाकरण पर संयुक्त प्रयास सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य समाज की संरचना निर्मित करने में अपनी अहम योगदान दें। कलेक्टर ने जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं के क्रियान्वयन में दोनों विभागों को आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य करने कहा।

कुपोषण मुक्ति के लिए अभियान चलाएं

कलेक्टर ने कुपोषण मुक्ति अभियान के लिए प्रभावी तरीकों से कार्य करने निर्देशित की। उन्होंने मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की जानकारी लेते हुए जिले में कुपोषण की वर्तमान दर और इसमें अग्रणी कमी की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि गंभीर कुपोषित बच्चों का एनआरसी में भर्ती कर उनके स्वास्थ्य में सुधार की ट्रैकिंग करें। बैठक में पूरक पोषण आहार पर जोर दिया गया। आंगनवाडियों में दिए जाने वाले रेडी-टू-ड्रिंक, भोजन की गुणवत्ता और वितरण की जांच करने निर्देशित की। इसके साथ ही मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, संस्थागत प्रसव, शत-प्रतिशत प्रसव अस्पतालों में करने कहा गया। कलेक्टर ने टीकाकरण बच्चों और गर्भवती महिलाओं के नियमित टीकाकरण की कवरेज रिपोर्टें संचित करने की भी निर्देश दिए। गर्भवती महिलाओं की समय पर भी निशे दिए। गर्भवती महिलाओं की समय पर की कड़ी चोटावनी दी गई।

पहचान करने कहा गया।



बैठक में प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना का प्रभावी क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए गए। पात्र हिताहियों को मिलने वाली राशि और लैबल प्रकरणों का निराकरण स्थिति की जांचकारी ली गई। इसी प्रकार महतारी वंदन योजना के तहत मिल रहे लाभ और डीबीटी की स्थिति की समीक्षा किया गया। कलेक्टर ने बैठक में एनीमिया मुक्त भारत बनाने की दिशा में सार्थक पहल करने कहा। किशोरी बालिकाओं और महिलाओं में खून की कमी को दूर करने के लिए आयुर्वेद-फॉलिक एसिड की गोलियों का वितरण करने निर्देशित की।

मैदानी क्षेत्रों का करें सघन दौरा

कलेक्टर ने फील्ड एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दी। ताकि कोई भी पात्र हिताहिली सेवा से वंचित न रहे। उन्होंने सभी डेटा शुद्धता के साथ ऑनलाइन पोर्टल (जैसे पोषण ट्रैकर) पर डेटा की रिवाल-टाइम एंटी प्रसुनिश्चित करने की। कलेक्टर ने कहा कि लक्ष्य प्राप्ति: सुनिश्चित किया जाए। जिन क्षेत्रों या ब्लॉकों में प्रदर्शन खराब है, वहां के अधिकारियों को समय सीमा के भीतर सुधार करने की कड़ी चोटावनी दी गई।

कलेक्टर ने अद्योसंरचना की समीक्षा की।

आंगनवाड़ी केन्द्रों में बिजली, पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि जब स्वास्थ्य और महिला बाल विकास विभाग मिलकर काम करते हैं, तो शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करने में बड़ी सफलता मिलती। जिले में आयोजित वजन त्वीहर के आंकड़ों की समीक्षा और कुपोषित बच्चों के चिह्नकन पर चर्चा किया गया।

कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। कलेक्टर ने सभी असेसे को कार्यप्रणाली में अनुशासन और जवाबदेही को लेकर एक कड़ा संदेश दी है। कलेक्टर ने बायोमेट्रिक्स में अनिवार्यता: उपस्थिति दर्ज करने कहा है। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के सभी अधिकारियों और कमचारियों को नियमित रूप से बायोमेट्रिक्स उपस्थिति दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। उपस्थिति दर्ज नहीं करने वाले अधिकारी कमचारियों के वैन आहरण पर रोक लगाए जाने निर्देश दिए गए हैं। साथ ही दृष्टी में अनियमितता और समय पर उपस्थिति दर्ज न करने वाले अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी जताते हुए, उनके आगामी आदेश तक वेतन रोकने का आदेश दिया गया है।

कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर तुमड़ीबोड़ के योगाभ्यास में लिया हिस्सा

15 दिवस के भीतर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए निर्देश

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

जिले में स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए संचालित विशेष योग अभियान के अंतर्गत कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने आज प्रातः डोंगरगांव विकासखंड के आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तुमड़ीबोड़ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों के साथ योगाभ्यास सत्र में शामिल हुए। उन्होंने योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवनशैली अपनाने तथा उपस्थित ग्रामीणों को नियमित योग करने के लिए प्रेरित किया।

कलेक्टर ने उपस्थित ग्रामीणों को मर्म के मौसम में स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी। उन्होंने लु से बचाव, पर्याप्त पानी सेवन, हल्का एवं पीठिक आहार लेने के साथ-साथ नियमित योग की दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने कहा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने दिनचर्या में कम से कम एक घंटा स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों के लिए अवसर निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि योग न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है और इसे अपनाकर कई बीमारियों से बचा जा सकता है। उन्होंने नागरिकों से अपने दैनिक जीवन में योग को शामिल करने



और स्वस्थ रहने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। कलेक्टर ने ग्रामीणों से चर्चा कर विकास

कार्यों एवं मूलभूत आवश्यकताओं को जानकारी ली। उन्होंने ग्रामीणों के शिकायत पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

तुमड़ीबोड़ स्टाफ को कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। उन्होंने स्टाफ को नियमित समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही 15 दिवस के भीतर स्वास्थ्य केन्द्र की सभी व्यवस्थाएं सुधार करने के लिए निर्देशित किया।

योग प्रशिक्षक द्वारा विभिन्न आसनों एवं प्राणायाम का अभ्यास कराया गया, जिसमें सभी ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अभियान का उद्देश्य 30 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को गैर-संचारी रोगों जैसे मधुमेह एवं उच्च रक्तचाप से बचाव एवं नियंत्रण के प्रति जागरूक करना है। प्रशिक्षित योग प्रशिक्षकों द्वारा मंडूकासन, वृक्षसन, भुजंगासन सहित विभिन्न योगासन एवं प्राणायाम कराए जा रहे हैं। साथ ही आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में बोपी एवं शुगर की निगरानी जांच कर आयुष चिकित्सकों द्वारा संतुलित आहार एवं जीवनशैली सुधार के संबंध में आवश्यक परामर्श भी दिया जा रहा है। इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एनआर नवतन, जिला कार्यक्रम प्रबंधक संदीप ताम्रकार, अस्पताल सलाहकार विकास गौरी एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित थे।

मामलों में न तो निर्माण कार्य शुरू किया गया और न ही स्वीकृत आवासों को पूर्ण किया गया। ऐसे हितग्राहियों द्वारा लगातार लापरवाही बरतने पर अब प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए नियमानुसार कानूनी प्रक्रिया के तहत वसूली एवं अन्य बंटात्मक

कार्रवाई प्रारंभ कर दी है, जिससे योजना में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। जिला प्रशासन ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रथममंत्री आवास योजना (ग्रामीण) केन्द्र एवं राज्य सरकार के एक महत्वाकांक्षी और जनकल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद परिवारों को पक्के आवास की सुविधा उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली राशि का दुरुपयोग किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। प्रशासन द्वारा ऐसे मामलों पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है और दोषी पाए जाने वाले हितग्राहियों के विरुद्ध सख्त एवं निरंतर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि योजना का लाभ सही पात्र व्यक्तियों तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंच सके।

प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी पर सख्ती, राशि का दुरुपयोग करने वालों पर वसूली शुरू

नई दृष्टिबिंदु / बेमतरा

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वीकृत राशि के दुरुपयोग के मामलों को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसे हितग्राही जिन्होंने निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने आवास का निर्माण कार्य उपयोग अन्य कार्यों में किया है, उनके विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी (राज्य) बेरला द्वारा विधियममत (वसूली) की कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और वास्तविक पात्र हितग्राहियों तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता पर अंकुश लगाया जा सके।



प्रशासनिक जानकारी के अनुसार, संबंधित हितग्राहियों को पूर्व में कई बार नोटिस जारी कर उन्हें अपना पक्ष रखने, स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने तथा शीघ्र आवास निर्माण कार्य प्रारंभ करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। इसके बावजूद अनेक

मामलों में न तो निर्माण कार्य शुरू किया गया और न ही स्वीकृत आवासों को पूर्ण किया गया। ऐसे हितग्राहियों द्वारा लगातार लापरवाही बरतने पर अब प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए नियमानुसार कानूनी प्रक्रिया के तहत वसूली एवं अन्य बंटात्मक

छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई के बच्चों ने विदेश में लहराया अपने देश का परचम



नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

मलेशिया में आयोजित 15वें साइलेंट नाइट इंटरनेशनल कराटे कप 2026 में छत्तीसगढ़ के भिलाई की अल्टीमेट कराटे क्लब के 6 बच्चों ने हिस्सा लिया। यह टूर्नामेंट मलेशिया के कुआलालंपुर के टीटी वॉसा स्टेडियम में 17 से 19 अप्रैल को हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़ से सिर्फ इन 6 बच्चों ने भाग लिया। श्रेयांश ठाकुर ने 11-12 वर्ष आयु वर्ग की -40 किलोग्राम कैटेगरी में श्रीलंका, इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया के प्रतिद्वंद्वियों को हराकर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। वहीं दक्ष शर्मा ने 8-9 वर्ष आयु वर्ग की +25 किलोग्राम कैटेगरी में मलेशिया, श्रीलंका, सिंगापुर और इंडोनेशिया को पराजित कर सिल्वर मेडल जीता। शोक पंडित ने 16-17 वर्ष आयु वर्ग की +76 किलोग्राम कैटेगरी में इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर को हराकर सिल्वर मेडल प्राप्त किया। टीम कुम्भिते में श्रेयांश ठाकुर,



केंद्रीय मंत्री के नाम पर खेल : कथित पत्रकार ने सिस्टम को बनाया निशाना, उगाही केस के बाद हुआ फरार



नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगतप्रकाश नड्डा के पत्र का रॉश दिखारकर निजी अस्पतालों से ठगी करने वाले आरोपी गुरमीत सिंह वाधवा को छावनी पुलिस ने हिरासत में लिया है। वाधवा का मेडिकल चेकअप सुपेला शासकीय अस्पताल में कराया जा रहा है। खबर लिखे जाने तक पुलिस ने अधिकृत गिरफ्तारी नहीं की है।

मामला कथित पत्रकार गुरमीत सिंह वाधवा से जुड़ा है, जिसने खुद को फोर्ब्स इंटरनेशनल नामक मैगजीन का मैनेजिंग एडिटर बताते हुए बड़ा खेल खेने की कोशिश की। उसने 28 नवंबर 2025 को केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के नाम का हवाला देते हुए राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखा और दावा किया कि उसे छत्तीसगढ़ के हर जिले में पांच-पांच अस्पतालों की जांच का जिम्मा सौंपा गया है।

इसी कथित अधिकार के आधार पर उसने भिलाई के एसबीएस अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए और कार्टवर्ड की मांग की। हैंगनी की बात यह रही कि इस पत्र के आधार पर स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया और जांच भी बैठा दी गई।

सोपनकर अग्रवाल को भी जांच का जिम्मा सौंपा गया था।

ने जब जांच की, तो वाधवा के सभी आरोप पूरी तरह निराधार निकले। अस्पतालों में सभी सुविधाएं मानकों के अनुरूप पाई गईं और मामले की कानून नित दिते हुए बंद कर दिया गया। वहीं से पूरे घटनाक्रम की असल परतें खुलनी शुरू हुईं।

जांच के नाम पर उगाही का आरोप

एसबीएस अस्पताल प्रबंधन ने 15 अप्रैल को एफआईआर दर्ज कर आरोप लगाया कि वाधवा ने पांच लाख रुपये की मांग की थी। रकम नहीं देने पर उसने आर्टीआई लाने और बदनाम करने की धमकी दी। शिकायत में यह भी कहा गया कि आरोपी पहले सुप्त में सलाह गए इंजेक्शन का बिल मांगता रहा और बाद में उसी बिल को फर्जी बताकर दबाव बनाते लगा। यहां तक कि अस्पताल प्रबंधन के चेंबर में घुसकर अभद्रता करने का भी आरोप है। एफआईआर दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस ने उसकी तलाश के लिए विशेष टीम गठित की है।

फर्जी पहचान, सदिग्ध नेटवर्क

जांच में यह भी सामने आया कि वाधवा को जांच उपायों किए गए

नगर पालिका की सामान्य सभा में हंगामा : आरोप-प्रत्यारोप की गूंज



नई दृष्टिबिंदु / खैरागढ़

सामान्य सभा की बैठक रठी हंगामेदार, विपक्ष के पार्षदों के साथ सचय सभापक्ष के पार्षदों ने दागे सवाल। नगर पालिका परिषद खैरागढ़ में सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर तीखे सवाल उठाए। बैठक के दौरान जमकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला।

पूरे समय माहौल गरमाया रहा और कई मुद्दों पर स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाने से असंतोष भी नजर आया। 82 प्लेसमेंट कर्मचारियों पर भाजपा पार्षद का सवाल, 52 से 82 कैसे हुए

भाजपा पार्षद चंद्रशेखर यादव ने 82 प्लेसमेंट कर्मचारियों को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा 52 से 82 कैसे हुए और 82 के 82 कर्मचारियों कहा काम करते हैं, किस-किस जगह पर तैनात हैं, उनके नाम क्या हैं, यह बताया जाए। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि किसी भी व्यक्ति के नाम पर पैसा निकाला जा रहा हो। उन्होंने रजिस्टर्ड दिखाते की मांग की। इस पर पालिका कर्मचारी टोडर सिंह ने समय मांगते हुए कहा कि रजिस्टर्ड उनके पास नहीं उपलब्ध नहीं है, वे कुछ समय बाद सदन में प्रस्तुत कर देंगे।

सामान्य सभा की बैठक में 20 में से 19 पार्षद उपस्थित रहे। एक पार्षद बार्ड क्रमांक 20 के दिलीप लखन अल्पस्थित रहे और शहर

में घूमते हुए नजर आए। उन्होंने बैठक का बहिष्कार करते हुए बैठक में आना जरूरी नहीं समझा और ने ही अनुपस्थिति की कोई सूचना दी।

टेकेदारों पर पक्षपात और अचूरे काम के आरोप

कांग्रेस पार्षद व उपाध्यक्ष अब्दुल रज्जाक खान ने आरोप लगाया कि भाजपा के ही रिश्तेदार टेकेदार के रूप में काम कर रहे हैं। वे अधिक काम ले लेते हैं, लेकिन समय पर पूरा नहीं करते। नया टेंडर आते ही फिर से काम उठा लेते हैं, जबकि जो टेकेदार काम कर रहे हैं, उनके पास अब काम नहीं बचा है। इससे निर्माण कार्य की गति धीमी बनी हुई है।

स्वच्छता और शौचालय व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल

चंद्रशेखर यादव ने स्वच्छता श्रृंगार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अभी तक इसका टेंडर क्यों नहीं हुआ। मार्च में टेंडर प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और अप्रैल से नई प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन कभी भी समय पर टेंडर नहीं किया जाता। इसके पीछे क्या कारण है, यह स्पष्ट किया जाए।

विधायक प्रतिनिधि कांग्रेस मनराखन देवांगन ने कहा कि शौचालयों की हालत बेहद खराब है। उन्होंने बताया कि वे स्वयं निरीक्षण कर चुके हैं और कहीं भी स्वच्छता नजर नहीं आई। आम लोगों को बहुत परेशानी होती है और नाक बंद करके अंदर जाना पड़ता है। इसी मुद्दे चंद्रशेखर यादव ने

आरोप लगाया कि प्लेसमेंट कर्मचारियों से ही शौचालय की सफाई करवाई जा रही है, जबकि टेकेदार को फायदा पहुंचाया जा रहा है और कमीशन लिया जा रहा है। उन्होंने पूछा कि बिना काम के पैसा कैसे निकल रहा है और चैक कौन काटता है।

नगर पालिका इंजीनियर को फटकार, भाजपा सभापति ने उड़ाए सवाल

चंद्रशेखर यादव ने नगर पालिका इंजीनियर को फटकार लगाते हुए कहा कि 20 जनवरी से पदस्थ होने के बावजूद वे कितने दिन कार्यालय आए हैं, यह स्पष्ट किया जाए। उनका वेतन कहां से बनता है और कौन बनाता है, यह भी सवाल उठाया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कार्यों में सुधार नहीं हुआ तो भिला प्रस्ताव भेजा जाएगा।

कांग्रेस पार्षद पुरुषोत्तम वर्मा ने सभापति अजय जैन से सवाल किया कि उनके कितने सदस्य हैं, कौन-कौन हैं और मंत्री कौन हैं। इस पर अजय जैन शांत खड़े रहे। इस पर वर्मा ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब जानकारी नहीं है तो सभापति बनने का क्या मतलब, पहले अपने दायित्व समझें।

नगर पालिका कार्यालय की बदहाल स्थिति उजागर

सांसद प्रतिनिधि राकेश गुप्ता ने कहा कि नगर पालिका के वायररूम की स्थिति भी खराब है। वहां वाटरी, मम और डाइरस तक उखड़ी हुई हैं। जब खुद कार्यालय की स्थिति ऐसी है तो अन्य जगहों की व्यवस्था कैसे

होगी, यह आसानी से समझा जा सकता है।

59 करोड़ की जल आवर्धन योजना पर सवाल

मनराखन देवांगन ने 59 करोड़ की जल आवर्धन योजना पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पूरे शहर में पाइपलाइन बिछ दी गई, सड़कों को खोद दिया गया, लेकिन एक बूंद पानी नहीं आ रहा। उन्होंने यह भी कहा कि पहले जल स्रोत से अनुमति ली जानी चाहिए थी। लालपुर में बने एनिकेट पर 2 करोड़ खर्च किए गए, धंधरा भी पानी स्टोर क्यों नहीं हो रहा है आज भी पानी की स्थिति संतोषजनक नहीं है।

अधिकारी की तैयारी और भाजपा की पर उठे सवाल

भाजपा पार्षद सुमित ठांडिया ने अधिकारी मनोज शुक्ला को फटकार लगाते हुए कहा कि उनके पास किसी भी प्रकार की तैयारी या रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने कहा कि अनुकंपा से नौकरों मिलने के बाद भी जिम्मेदारी नहीं निभाई जा रही है और वरिष्ठ अधिकारियों से सीखने की जरूरत है।

सभापति ने अपने ही वार्ड की सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जताई

चंद्रशेखर यादव ने अपने ही वार्ड की सफाई व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि शौचालय की सीट टूटी हुई है, गेट खराब है और नालियां भरी हुई हैं। इसके बावजूद टेकेदारों को समय पर भुगतान किया जा रहा है, जो गंभीर मामला है।

नगर पालिका अध्यक्ष ने भारी हंगामे और आरोप प्रत्यारोप के विच किया बजट पेश

सामान्य सभा की बैठक के अंत में अध्यक्ष गिरजा चंद्राकर ने बजट पेश किया, जिसमें कांजी हाउस, मुक्तियाम उन्नयन और प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाएं शामिल थीं। इस दौरान मनराखन देवांगन ने पूछा कि कांजी हाउस कहाँ बनेगा और इसकी लागत कितनी होगी, लेकिन अध्यक्ष औरकाई जवाब नहीं दे सकी। उन्होंने मुक्तियाम के निर्माण और खर्च पर भी सवाल उठाए, है लेकिन इस पर भी संतोषजनक जानकारी नहीं दी गई। इसपर मनराखन देवांगन ने कहा पहले खुद पड़ से बजट को कुछ भी पास नहीं करना है।

सीएमओ का एक ही जवाब, मैं तो अभी

किसी भी कार्य को लेकर जब सीएमओ से सवाल पूछा गया तो, वही अधिकारी उनसे स्पष्ट जवाब की अपेक्षा की गई। हालांकि, लगभग हर प्रश्न पर उनका एक ही जवाब रहा—कि वे अभी नया आया हुआ हैं और हाल ही में यहां पदस्थ हुआ है।

पारदर्शिता और कार्यपाली पर खड़े हुए सवाल

कुल मिलाकर बैठक में पारदर्शिता, कार्यपाली और विकास कार्यों को लेकर कई गंभीर प्रश्न खड़े हुए, जिनका समाधान फिलहाल अधूरा नजर आया।

GOSWWAMI FLEX PRINTING
ADVERTIZER
भिलाई में सबसे सस्ता, सबसे अच्छा
• Hoardings • Flex Banner • Vinyl Printing
• One Way Vision • Glow Sign Board
93290-13334, 74711-15735
goswamiflex@gmail.com
Address : 3rd Floor Shop No.1, Arora Tower, M.C. Market

महत्वपूर्ण सूचना! हमारे पाठकों के लिए
नई दृष्टिबिंदु
सांध्य देनिक नई दृष्टिबिंदु का E-Paper भी तैयार है।
प्रतिदिन **शाम 4:00 बजे** पेपर नई दृष्टिबिंदु के गुगल के साइट **Nayai Drishtibindu पर अपलोड हो जाता है। सभी पाठकों से आग्रह है कि प्रतिदिन शाम 4:00 बजे साइट पर Nayai Drishtibindu E-Paper सर्व करवा दे सकेंगे।**
इस तेजी से एक सदिग्ध पत्र पर कार्टवर्ड हुई, उसने स्वास्थ्य विभाग की कार्यपाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यह मामला इस बात का संकेत है कि प्रभाव का भय दिखाकर सिस्टम को किस हद तक मोड़ा जा सकता है। फिलहाल पुलिस जांच जारी है, लेकिन यह घटनाक्रम साफ संकेत दे रहा है कि यदि ऐसे फर्जी प्रभाव और दबाव के खेल पर समय रहते रोक नहीं लगी, तो व्यवस्था को प्रभाव कर बड़े स्तर पर खेल खेलें जा सकते हैं।
G Google
NAYI DRISHTIBINDU E-PAPER
शाम 4 बजे से पढ़ें
नई दृष्टिबिंदु

Baked by Suhani
Premium Homemade Cakes & Desserts
Birthday Cakes
Anniversary Cakes
Custom Theme Cakes
Serving Bhillai & Durg
Serving Bhillai & Durg
baked.by.suhani
posts, message
Suhani Singh
Premium Homemade Cakes & Desserts
Serving Bhillai & Durg
DM for Order
Followed by _s_andeep
Follow Message
Order Now:
@baked.by.suhani
MO.6263734520